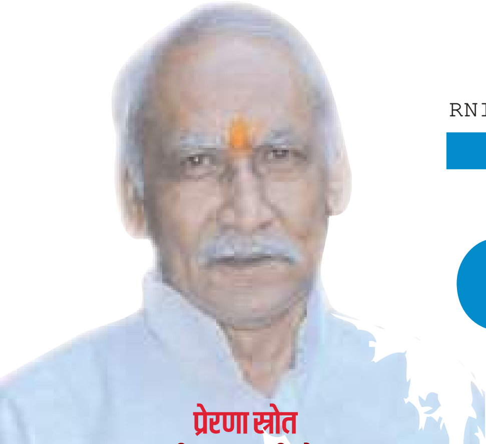
प्रेरणा स्रोत
स्व. श्री यशवंतजी घोड़ावत

RNI No. MPHIN/2018/76422

माही की गूंज

बेबाकी के साथ...सच

Www.mahikigunj.in, Email-mahikigunj@gmail.com

वर्ष-04, अंक - 10 (साप्ताहिक) | खवासा, गुरुवार 09 दिसम्बर 2021 | पृष्ठ-8, मूल्य -5 रुपए

सुविचार

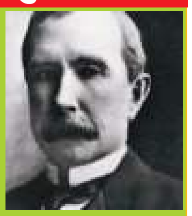

अगर अमीर बनना ही तुम्हारा मात्र एक लक्ष्य है, तो तुम इसे कभी हासिल नहीं कर पाओगे।

जॉन डी रॉकफेलर

शिवराज के राज में सब कुछ मुमकिन...!

मांग भरवाकर व मुंह में चांदी के चम्मच ठुसवाकर जिला प्रशासन ने एक ही दिनांक व एक ही पत्र क्रमांक पर आपत्ती व अनापत्ति के दो प्रमाण-पत्र किए जारी

कलेक्टर सोमेश मिश्रा जिले में भ्रष्टाचार के गढ़ रहे नए-नए आयाम, नतीजन डीजल माफियाओं की भी बल्ले-बल्ले

माही की गूंज टीम के साथ संजय भटेवरा की रिपोर्ट

शिवराज सरकार में सब कुछ मुमकिन है... कि बात कहीं जाती है। जी, हां यह बात सही ही साबित हो रही है कि, शिवराज सरकार में प्रशासन निरंकुश होकर जिले में भ्रष्टाचार व अनिमितताओं के नए-नए आयाम गढ़े जा रहे हैं...

वही शिवराज सरकार कहती है माफियाओं को जड़ मूल से खत्म किया जाएगा, तो प्रशासन व्यवस्था में कोई भी अनियमितताओं पाई जाती है तो उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। पर यह बस सिर्फ लोक लुभावन ही साबित होकर शिवराज सरकार में अनियमितताए व भ्रष्टाचार के ऐसे-ऐसे आयाम गढ़े जा रहे हैं जो शायद शिवराज सरकार में ही प्रशासनिक पकड़ नहीं होने के कारण सब कुछ मुमकिन हो रहा है... !

बात जिले में सिर्फ डीजल माफियाओं के मुद्दे की ही करे तो शिवराज सरकार के उनके अधीनस्थ व निरंकुश प्रशासन बायोडीजल के नाम पर अपने मुंह मांगी मांग का सिंदूर भरवाकर अपने मुंह में चांदी की चम्मच ठुसवाकर खुलेआम नकली डीजल बिकवा रहा है। वही कलेक्टर सोमेश मिश्रा के रहमो-करम से प्रशासनिक खानापूर्ति ऐसी हो रही है कि, मानो ''हम ही राजा है और हम ही प्रजा'' यानी शिवराज सरकार में कुछ भी करो ना कोई देखने वाला न कुछ करने वाला। नतीजन शिवराज सरकार में सब कुछ मुमकिन की बात को चरितार्थ कर डीजल माफियाओं की बल्ले-बल्ले हो रही है और प्रशासनिक आला अधिकारि के पैर से लेकर सिर तक भ्रष्टाचार रूपी चासनी में डुबकी लगा रहे हैं।

माही की गूंज में सतत् बायोडीजल के नाम से बेच रहे नकली डीजल व डीजल माफियाओ तथा प्रशासनिक गठजोड़ को प्रकाशित किया, जिससे प्रशासनिक हड़कंप मचने के साथ माफिया भी बौखलाए हुए हैं।

हमारे समाचारों के साथ ही एक के बाद एक बाते सामने निकल कर आ रही है, जिसमें जिला प्रशासन के आला अधिकारी से लेकर कलेक्टर तक भी माफियाओं को संरक्षण देकर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इतना ही नहीं चांदी की चम्मच ठुसवाकर अपनी मुंह मांगी मांग का सिंदूर भरवा कर सरकारी मिशनरी का दुरूपयोग ऐसे कर रहे हैं जैसे अपने बाप की बपौती हो। जिसका एक उदाहरण हमारे सामने ऐसा आया है कि, जिसमें संबंधित अधिकारी से लेकर कलेक्टर तक बडी कार्रवाई हो सकते हैं। लेकिन हम यह अच्छी तरह से जानते हैं कि, भ्रष्ट तंत्र में अधिकारी अपनी हर निचले स्तर की अनियमितताएं उजागर होने के बाद भी अपने आप को सही साबित करने के लिए बेतुके जवाब के साथ ही ये सरकार के सामने सही साबित हो जाते हैं।

मामला कुंदनपुर से सटे राणापुर मार्ग पर ग्राम सरुडिया में इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड के पेट्रोल-डीजल पंप की मंजूरी का है। जिसमें इंडियन ऑयल कार्पोरेशन की विज्ञप्ति के बाद काकरादरा ग्राम के गौरव पिता उदेसिंह नायक के नाम से पेट्रोल पंप अलार्टमेन्ट हुआ जिसमें प्रथम दृष्टिया ही कलेक्टर कार्यालय की एनओसी में ही ऐसा झोलमाल किया की सारे नियम कायदों को ताक में रख सरकार से बेखौफजिला प्रशासन ने आपत्ती प्रमाण-पत्र सर्वप्रथम जारी किया और बाद में उसी पत्र क्रमांक व उसी दिनांक पर सांठगांठ के साथ अभी प्रमाणित (एनओसी) पत्र जारी कर दिया।

पत्र क्रमांक 1106/लीडर-1/2020 झाबुआ 6 अक्टूबर 2020 एवं आवेदक गौरव नायक के आवेदन 11 नवंबर 2020 के संदर्भ में कार्यालय सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश झाबुआ मध्य प्रदेश से पत्र क्रमांक 45/नग्रानि/अना./2021, 28 जनवरी 2021 को प्रतिलिपि कलेक्टर जिला झाबुआ के प्रेषित कर विषय, ग्राम सरुडिया (राणापुर-कुंदनपुर रोड़) तहसील राणापुर जिला झाबुआ में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में पत्र जारी किया। जिसमें उल्लेख किया कि, सीडीआरएसएम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इंदौर द्वारा आवेदक गौरव पिता उदेसिंह नायक निवासी काकरादरा द्वारा ग्राम सरुडिया (राणापुर-कुंदनपुर रोड) स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 578, 579, 580, 581, 582, 583 कुल रकबा 0.620 हें. में से भूमि क्षेत्रफल 1225 वर्ग मीटर भूमि पर प्रस्तावित रिटेल आउटलेट पेट्रोल पंप हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया। प्रकरण के सलंगन दस्तावेजों के प्रशिक्षण एवं स्थल निरीक्षण से यह की प्रश्नाधीन स्थल मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम-2012 के नियम-53(3)(4)(ख) की तालिका के कालम क्रमांक 07 में संयोजन से न्यूनतम दूरी 100 मीटर की पूर्ति नहीं करता है। अतः प्रश्नाधीन भूमि पर नवीन रिटेल आउटलेट पेट्रोल पंप प्रयोजन हेतु कार्यालय द्वारा अनापत्ति प्रदाय किया जाना उचित नहीं है। के साथ आपत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया।

उक्त पत्र सूचनार्थ पत्र क्रमांक 46 पर सीडीआरएसएम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से आवेदक गौरव नायक को भी प्रेषित किया।

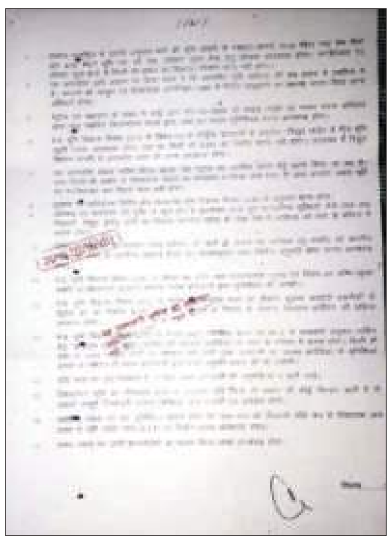

28 जनवरी 2021 पत्र क्रमाक 45-46 पर ही दुसरे पत्र मे 3 पेज मे किया अनापत्ति पत्र जारी

28 जनवरी 2021 को पत्र क्रमाक45-46 पर आपत्ति प्रमाण-पत्र किया जारी।

आईटीआई की जानकारी के बाद हुआ चौंकाने वाला खुलासा

उक्त आपत्ती प्रमाण-पत्र जारी करने के बाद क्षेत्र में यह सार्वजनिक हो गया था कि, गौरव नायक का प्रस्तावित पेट्रोल पंप शासकीय गाइडलाईन में मुख्य मार्ग से 100 मीटर के दायरे में आने के कारण कलेक्टर कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं हो कर आपत्ति प्रमाण पत्र जारी हुआ है और अब गौरव नायक का पेट्रोल पंप नहीं खुल सकता। जारी आपत्ति प्रमाण-पत्र भी गौरव नायक के माध्यम से सार्वजनिक हो चुका था, बावजूद कुछ समय के बाद ही सरुडिया में गौरव नायक ने पेट्रोल पंप खोलने हेतु निर्माण कार्य शुरू कर दिया। जिससें क्षेत्रवासी अचंभित होकर सोचने लगे कि, जब कार्यालय सहायक संचालक नगर तथा निवेश झाबुआ द्वारा आपत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया गया था, तो आखिर ऐसा क्या तिलिस्मी जादू रूपी आदेश जारी हुआ कि, गौरव ने कलेक्टर की एनओसी नहीं मिलने पर भी पेट्रोल पंप का निर्माण कार्य चालू कर दिया।

इसी संशय को दूर करने हेतु ग्राम कुंदनपुर के आरटीआई कार्यकर्ता धर्मेंद्र राठौर ने 17 मार्च 2021 को संबंधित पंप की मंजूरी एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र की सत्य प्रतिलिपि के साथ जानकारी निकाली, तो 6 अप्रैल 2021 को पत्र क्रमांक 119 कार्यालय सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश झाबुआ के प्रभारी अधिकारी ने सत्य प्रतिलिपि उक्त पेट्रोल पंप संबंधित दी। तो तिलस्मी जादू के साथ उजागर हुआ कि, जिस दिनांक 28 जनवरी 2021 के उसी पत्र क्रमांक 45-46 पर जिस पत्र क्रमांक पर आपत्ति पत्र जारी किया था, उसी एक ही पत्र क्रमांक पर अभिप्रमाणित (अनापत्ति) पत्र जारी कर दिया गया। जिसमें जीएल वर्मा साहब ने कलेक्टर के नाम प्रति जारी कर अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करते हुए उल्लेख किया कि, राणापुर से कुंदनपुर जाने वाला मार्ग स्थित दर्शाए अनुसार मार्ग विस्तार हेतु 15.85 मीटर भूमि छोड़ना आवश्यक होगा, भूमि छोड़ने के संबंध में संबंधित विभाग से अभीमत प्राप्त करना अनिवार्य होगा यदि उनके प्रावधानों के अंतर्गत इससे अधिक भूमि मार्ग विस्तार हेतु छोड़ना हो तो छोड़नी होगी के साथ 19 पॉइंट के साथ 3 पेज में अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी कर प्रशासनिक व्यवस्थाओं को अपने बाप की बपौती मानकर हस्ताक्षरित कर एक ही पत्र क्रमांक पर एक पत्र पर आपत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया, तो दूसरे पत्र में अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी कर 19 पॉइंट में इसे पॉइंट भी दर्शाई गए कि, मामला भविष्य में न्यायालय तक भी जाए तो अपने दिये तर्कों के साथ पतली गली से अधिकारी बच जाएगा।

सर्वप्रथम पत्र में 100 मीटर की दूरी व नियम का हवाला देकर आपत्ति पत्र जारी किया। तो दूसरे पत्र में उस सड़क दूरी को 85 प्रतिशत दायरा कम कर दिया गया। एक ही दिनांक में आपत्ति और अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी कर कलेक्टर के नाम से प्रति प्रेषित की गई लेकिन कलेक्टर द्वारा इस पत्र के संबंध में कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। तय है ऐसे खेल कलेक्टर के अनधिकृत निर्देशों के साथ ही कार्यालयो से सरकारी मिशनरी का दुरुपयोग कर अपने निजी स्वार्थ के साथ अपनी मांग पूरी कर चांदी की चम्मच ठुस-ठुसवाकर सिंदूर भरवाने वाले इस तरह की अपनी कारस्तानिया दिखा रहे।

उक्त कारस्तानिया प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिन्ह तो लगाती है, परंतु सरकार की नाकामियों को भी प्रदर्शित करती है।

मामले में हुई भोपाल तक शिकायत

खैर शिकायतकर्ता ने मामले को इंडियन ऑयल प्राइवेट लिमिटेड से लेकर भोपाल से लेकर बाम्बे तक संबंधित वरिष्ठ कार्यालयों में शिकायत की है। मामले में जांच भी शुरू हो चुकी है पर आईएस स्तर तक के अधिकारी इस जांच को अपनी बुद्धिमत्ता से किस स्तर तक प्रभावित करेंगे यह आगे देखने का विषय रहेगा।

प्रभारी सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश अधिकारी झाबुआ जीएस वर्मा से इस संदर्भ में माही की गूंज की बात हुई, तो साहब कहते हैं लिपिकीय की त्रुटी वश पत्र जारी हुए है।

यह शब्दों की त्रुटी नहीं बल्कि आप एक जवाबदार अधिकारी द्वारा ही एक दिनांक व एक ही पत्र क्रमाक पर दो पत्रों का इस तरह से जारी करना त्रुटी कैसे माना जाए ?

उत्तर :- यह लिपिकीय त्रुटि है, अधिकारी सिर्फ साइन करता है और फ़ाइल देखता है, आवक-जावक लिपिकीय ही करता है

लिपिकीय तो अधिकारी के आदेश का ही पालन करेगा जो आपने आदेश दिया होगा वही लिपिकीय ने किया होगा न सर ? जिसके बाद साहब के पास जवाब नहीं रहा तो

उत्तर :- वर्क लोड के कारण इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, शिकायत हुई है उसकी जांच चल रही है, इसका जवाब भी दे दिया है।

पुलिस कमिश्नर सिस्टम को सीएम जल्द दे सकते है मंजूरी

भोपाल। मध्य प्रदेश में पुलिस कमिश्नर सिस्टम को लेकर इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। जानकारी अनुसार पुलिस कमिश्नर सिस्टम का फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो गया है और पंचायत चुनाव से पहले मध्य प्रदेश सरकार इसको मंजूरी दे सकती है। एक हफ्ते के अंदर इसकी अधिसूचना जारी की जा सकती है। सरकार का यह फैसला चुनाव पर असर डाल सकता है।

दरअसल, बीते दिनों सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर और भोपाल में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने का फैसला किया था। इसी बीच पंचायत चुनाव 2021 की तारीखों का ऐलान हो गया। अब खबर मिल रही है कि, मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिस कमिश्नर प्रणाली की अधिसूचना का ड्राफ्ट फाइनल कर लिया है और अब बस सीएम शिवराज की मंजूरी का इंतजार है। सिस्टम के लागू होते ही दोनों शहरों के पहले पुलिस कमिश्नर और अन्य अफसरों की पोस्टिंग का आदेश भी जल्द जारी किया जा सकता है।

संभावना जताई जा रही है कि, यूपी दौरे से पहले सीएम शिवराज इस पर सहमति की मोहर लगा सकते है और दोनों शहरों में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हो जाएगा। चुंकी 13 दिसंबर को वे यूपी के बनारस जाएंगे और यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक लेंगे। इसमें राज्यों के नवाचार व विकास के कामों का प्रेजेंटेशन होगा, ऐसे में अटकलें तेज हो गई है कि दौरे से पहले सिस्टम को प्रदेश में लागू किया जा सकता है और पुलिस अफसरों को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है।

सीडीएस का चौपर क्रैश, 13 लोगों की गई जान, डीएनए टेसिं्टग से होगी शवों की पहचान

कुन्नूर, एजेंसी। तमिलनाडु के कुन्नूर में बुधवार को वायुसेना का चौपर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वायुसेना के एमआई-17 हेलिकॉप्टर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) बिपिन रावत, उनकी पत्नी सहित 14 लोग सवार थे। जानकारी अनुसार हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है। क्रैश के बाद हेलिकॉप्टर में आग लगने की वजह से शव बुरी तरह झुलस गए हैं। ऐसे में शवों की पहचान के लिए डीएनए जांच कराई जाएगी।

जनरल बिपिन रावत को ले जा रहा भारतीय वायुसेना का हेलिकॉप्टर तमिलनाडु के कुन्नूर के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि, यह हादसा कोहरे के कारण कथित तौर पर कम दृश्यता की वजह से हुआ। समाचार लिखे जाने तक वायुसेना ने जनरल रावत की हालत को लेकर कोई जानकारी नहीं दी। वायुसेना का एमआई-17वीएच हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और इस हादसे के कारण का पता लगाने के लिए 'कोर्ट ऑफ इंक्वायरी' के आदेश दिए गए हैं। हेलिकॉप्टर ने कोयंबटूर के पास सुलुर वायुसेना अड्डे से उड़ान भरी थी।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने घटना पर दुख व्यक्त किया और संकेत दिया कि, हेलीकॉप्टर में 14 लोग थे। टेलीविजन पर दिखाई जा रही फुटेज में, बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हेलिकॉप्टर से आग की लपटें उठती दिखीं। हेलिकॉप्टर के मानव बस्ती से दूर दुर्घटनाग्रस्त होने से एक बड़ी त्रासदी होने से हालांकि बच गई। दुर्घटनास्थल पर भारतीय वायुसेना के हेलिकॉप्टर के क्षतिग्रस्त और जले हुए टुकड़े बिखरे पड़े थे।

स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि, उन्होंने तेज आवाज सुनी, जाहिर तौर पर हादसे की आवाज थी, और बाद में हेलिकॉप्टर में आग लगी, जिसमें उसमें सवार कुछ लोग गंभीर रूप से झुलस गए। सीडीएस जनरल रावत वेलिंग्टन में 'डिफेंस सर्विसेज कॉलेज' (डीएससी) जा रहे थे। हेलीकॉप्टर नीलगिरि जिले के पर्वतीय क्षेत्र में कुन्नूर के निकट कातेरी-नंजप्पनचथिराम इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को लेकर हेलिकॉप्टर कोयंबटूर के सुलुर से वेलिंग्टन में डीएससी की ओर जा रहा था, जहां जनरल रावत, थल सेनाध्यक्ष एमएम नरवणे के साथ बाद में एक कार्यक्रम में भाग लेने वाले थे।

छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय अब होगा राजा शंकर शाह विश्विद्यालय, कैबिनेट से मिली मंजूरी

भोपाल।

छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय अब शंकर शाह विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाएगा। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसकी पहले ही घोषणा कर चुके हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में कैबिनेट ने राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों के लिए गांवों के पुनर्वास के लिए प्रति परिवार मुआवजे की राशि भी 10 लाख से बढ़कर 15 लाख रुपए भी कर दी।

कैबिनेट ने छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय किए जाने के प्रस्तावित संशोधन विधेयक के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इन दिनों राज्य की सियासत में आदिवासी बड़ा मुद्दा बना हुआ है। जनजातीय वर्ग के जननायकों के नाम पर अनेक स्थानों के नामकरण किए जा रहे हैं। इसी क्रम में छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नामकरण किया गया है। इससे पहले भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति के पर नाम किया गया और बिरसा मुंडा के जन्म दिन को गौरव दिवस के रूप में मनाया गया। इसके अलावा इंदौर में टंट्या भील की याद में भव्य कार्यक्रम हुआ।

कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रीय उद्यानों व अभयारण्यों (संरक्षित क्षेत्रों) और टाइगर रिजर्व के कॉरिडोर से ग्रामों के पुनर्वास का मुआवजा प्रति परिवार 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए करने को मंजूरी भी दी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, ग्वालियर को एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिये ग्राम लोहारपुर में स्थित 57.952 हेक्टेयर शासकीय भूमि आवंटित करने का निर्णय भी कैबिनेट की बैठक में लिया गया।

कैबिनेट ने लोक सेवा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान की सांगठनिक संरचना में अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति की सेवा शर्तों के संबंध में संशोधित आदेश को भी मंजूरी दे दी।

इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई, भोपाल-इंदौर में सेज ग्रुप के ठिकानों पर छापे

भोपाल। इनकम टैक्स विभाग ने सेज ग्रुप के भोपाल और इंदौर ठिकानों पर छापा मारा है। जानकारी अनुसार, आईटी की टीमों ने एजुकेशन और कंस्ट्रक्शन से जुड़े से सेज ग्रुप के भोपाल-इंदौर सहित अन्य ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। सेज ग्रुप पर 10 साल पहले भी इनकम टैक्स का छापा पड़ा था। भोपाल में शिक्षा समूह व बिल्डर के एक दर्जन ठिकानों पर पड़ताल की जा रही है। वही सागर कॉलेज, सागर बिल्डर व डेवलपर के घर, दफ्तर और कॉलेज पर कार्यवाई जारी है। सोशल मीडिया पर यह जानकारी तेजी से वायरल हुई है और भोपाल में सेज ग्रुप के अरेरा कॉलोनी, अयोध्या बायपास सहित कुछ अन्य ठिकानों पर यह कार्रवाई की जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सेज ग्रुप के अलावा एक अन्य एजुकेशन ग्रुप पर भी छापे की सूचना है लेकिन इस बारे में अभी पुष्टि नहीं हो सकी है। वहीं, सेज ग्रुप के लिए पहुंची टीमों की कार्रवाई के लिए मंगलवार को आयकर ऑफिस में कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकें हुई थीं।

बिगुल बजा लेकिन संशय बरकरार

माही की गूंज,झाबुआ।

लोकतंत्र की सबसे छोटी लेकिन महत्वपूर्ण इकाई ग्राम पंचायत के चुनाव जो कि लंबे समय से कोविड-19 संक्रमण के कारण टाले जा रहे थे, आखिरकार घोषित तो हो गए हैं लेकिन अभी भी सबके मन में संशय बरकार है कि, चुनाव घोषित तारीखों के दिन होंगे या नहीं होगे...? संशय के दो कारण हैं पहला कानूनी दावपेंच तथा दूसरा कोविड-19 के नए वेरियंट ओमीक्रोन को लेकर है। डेल्टा वेरियंट की दूसरी लहर की भयावहता की कल्पना मात्र से मन विचलित हो जाता है, ऐसे में तीसरी लहर की आशंका ने न केवल सरकार बल्कि आम आदमी के चेहरे पर चिंता की लकीर खींच दी है, वही पुराने परिसीमन व आरक्षण के सरकार के फैसले पर कानूनी दांवपेच जारी है। अब फैसला किसके पक्ष में आएगा इसका तो पता जल्द ही लग जाएगा लेकिन तमाम आशंकाओं-कुशंकाओं के बीच चुनावी मैदान में किस्मत आजमाने के लिए तैयार बैठे नेताओं के चेहरे अवश्य खिल गए हैं। उनकी दिनचर्या में परिवर्तन हो गया है, विनम्रता की प्रतिमूर्ति बने ये नेता सुबह से देर शाम तक गली मोहल्ले में चक्कर काटते नजर आ रहे हैं, बड़े बुजुर्गों से अभिवादन करना इनकी दिन चर्चा में शामिल हो चुका है।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है, धरने, रैली, सभाएं आदि बगैर अनुमति के प्रतिबंधित हो गए हैं। नए कार्यों पर रोक रहेगी पुराने जारी रहेंगे ये प्रतिबंध नगरीय निकायों की सीमाओं के अंतर्गत नहीं है।

क्या है पूरा चुनावी कार्यक्रम

निर्वाचन आयोग द्वारा जारी चुनावी कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में 3 चरणों में मत डाले जाएंगे।

जिसने प्रथम चरण पेटलावद के लिए

13 दिसम्बर से 20 दिसम्बर तक नामांकन,
23 दिसम्बर तक नाम वापसी
6 जनवरी को मतदान सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक

द्वितीय चरण में थांदला

13 दिसम्बर से 20 दिसम्बर से नामांकन,
23 दिसम्बर तक नाम वापसी
28 जनवरी को मतदान सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक

तृतीय चरण झाबुआ,राणापुर व रामा के लिए

30 दिसम्बर 2021 से नामांकन,
10 जनवरी तक नाम वापसी
16 फरवरी को मतदान सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक

इसके अलावा अलीराजपुर जिले में एक ही चरण में 16 फरवरी को मतदान होगां। पंच तथा सरपंच के मतों की गिनती मतदान समाप्ति के पश्चात संबंधित मतदान केंद्रों पर ही की जाएगी, लेकिन परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा। परिणाम ब्लॉक मुख्यालय से आयोग द्वारा तय की गई तारीख के बाद घोषित किया जाएगा तथा विजयी अभ्यर्थीयो को प्रमाण-पत्र भी ब्लॉक मुख्यालय से दिए जाएंगे। जनपद तथा जिला पंचायतों के निर्वाचन इलेक्ट्रॉनिक केटिंग मशीन इवीएम के माध्यम से किये जाएंगे तथा इनके परिणामों की घोषणा 23 फरवरी को की जाएगी। पंच के लिए सफेद मतपत्र, सरपंच के लिए हरा मतपत्र, जनपद सदस्य के लिए पीला मतपत्र तथा जिला पंचायत के लिए गुलाबी मतपत्र का इस्तेमाल किया जाएगा। पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान कोविड-19 के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा।

कलेक्टर-एसपी ने किया दौरा पंचायत चुनाव को लेकर दिए निर्देश, टीकाकरण के लिये की अपील

माही की गूंज मेघनगर। आगामी पंचायत चुनाव की तैयारियों के साथ लोगों को टीकाकरण पर जागरूक करने के लिए कलेक्टर सोमेश मिश्रा और एसपी आशुतोष गुप्ता ने मेघनगर विकासखंड का दौरा किया। इस दौरान वो मेघनगर के बालक उच्चतर विद्यालय पहुचे यहां पर उन्होंने स्ट्रांग रूम के साथ 4 मतदान केंद्रों का निरीक्षण भी किया। उन्होंने स्थानीय अधिकारियों, कर्मचारियों को निर्देश भी दिए साथ ही आम जनता से पूर्ण टीका लगाने के लिए अपील भी की। स्ट्रांग रूम का निरीक्षण करते हुए एसपी श्री गुप्ता और कलेक्टर श्री मिश्रा ने मेघनगर के सीएमओ विकास डाबर, तहसीलदार रविंद्र चौहान के साथ एसडीएम अंकिता प्रजापति को निर्देश दिए कि वह शासन के नियमों के अनुरूप ग्रामीण अंचलों के मतदान केंद्रों का दौरा कर सारी व्यवस्थाए सुचारू हो इसके लिए काम करें। साथ ही टीकाकरण पर भी लोगो को जागरूक कर प्रेरित करे।

कलेक्टर ने बताया कि, विकासखंड या पूरे झाबुआ जिले की बात करें तो कोरोना का पहला टीके का शतप्रतिशत लक्ष्य को हम पूरा करने के बहुत पास है, लेकिन कोरोना के दूसरे डोज को लेकर हम चाहते है कि, लोग दूसरा टीका लगवाए और लोगों को इस टीके को लगवाने के लिए जागरूक भी करें, साथ ही आगामी पंचायत निर्वाचन चुनाव को लेकर आम जनता निष्पक्ष रुप से प्रशासन का सहयोग भी करें।

महाविद्यालय झाबुआ में कोविड–19 वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन

माही की गूंज, झाबुआ।

शहीद चन्द्रशेखर आजाद, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झाबुआ में मप्र शासन, उच्च शिक्षा विभाग भोपाल के निर्देशानुसार विद्यार्थियों की 100 प्रतिशत उपस्थिति के साथ अध्यापन कार्य प्रारंभ किया गया है। इस संबंध में कोविड-19 के बचाव हेतु सभी छात्र-छात्राओं को कोविड-19 वैक्सीनेषन के दौनों डोज लगाना अनिवार्य किया गया है। प्रदेश में जारी महा-वैक्सीनेशन अभियान के तहत् महाविद्यालय में अध्ययनरत ऐसे छात्र-छात्राऐं जिन्होंने किसी कारण से कोविड-19 वैक्सीनेशन का प्रथम या द्वितीय डोज नहीं लगवाया गया है। उनके लिए बुधवार को कोविड-19 टीकाकरण शिविर का आयोजन किया। संस्था प्रमुख एवं प्राचार्य डॉ. जे. सी. सिन्हा ने बताया कि छात्र-छात्राओं में कोविड-19 के प्रभाव के प्रति जागरूकता लाने के लिए जून 2021 से सतत् विभिन्न उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है । महाविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी डॉ. रविन्द्र सिंह ने कहा कि आगे भी टीकाकरण शिविर का आयोजन किया जाता रहेगा जब तक कि सभी छात्र-छात्राओं को कोविड-19 वैक्सीन का प्रथम एवं द्वितीय डोज नहीं लग जाता है। टीकाकरण शिविर में एल.एस. डोडिया सीएमओ नगर पालिका झाबुआ, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. राहुल गणावा के साथ पुष्पा भूरा तथा नरमा मंडोडिया स्वास्थ्य कार्यकर्ता, अनिता डामोर, दीपिका गवली आशा कार्यकर्ता व सीता बारिया आंगनवाडी कार्यकर्ता ने उपस्थित रहकर टीकाकरण कार्य सम्पन्न कराया।

महाविद्यालय कोविड-19 प्रभारी डॉ. कौशलेश पाठक ने अवगत कराया कि आज आयोजित टीकाकरण शिविर में कुल 72 छात्र-छात्राओं को कोविड-19 वैक्सीनेशन का द्वितीय डोज लगवाया गया। टीकाकरण शिविर में महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉ. संजू गांधी, सहायक प्राध्यापक डॉ. प्रदीप कटारा, डॉ. रीता गणावा, डॉ. मनीषा सिसोदिया, डॉ. रंजना रावत, डॉ. कुंवरसिंह चौहान, प्रो. दिलीप राठौर, डॉ. संगीता भाबोर, डॉ. हरिओम अग्रवाल, डॉ. रवि विष्वकर्मा, प्रो. पंकज कुमार बारिया, प्रो. अजय कुमार, प्रो. अंतिम कलवार एवं प्रो. रितेष तंवर ने उपस्थित रहकर छात्र-छात्राओं के टीकाकरण में सहयोग प्रदान किया।

केश शिल्पी कल्याण बोर्ड का युवा चेयरमेन निलेश परमार 'सेन' को नियुक्त करने की मांग

सर्व सेन समाज ने मिलकर मप्र के मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम झाबुआ को सौंपा ज्ञापन

माही की गूंज, झाबुआ।

भारतीय सर्व सेन समाज एवं मप्र के सर्व सेन समाज के आव्हान पर सर्व सेन समाज झाबुआ द्वारा भी मंगलवार को मप्र के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के नाम ज्ञापन एसडीएम झाबुआ लक्ष्मीनारायण गर्ग को सौंपा गया। जिसमें सभी ने सामूहिक रूप से मांग की है कि केश शिल्पी कल्याण बोर्ड का युवा चेयरमेन निलेश परमार 'सेन' को शासन स्तर से मनोनीत किया जाए।

जानकारी देते हुए भारतीय सेन समाज झाबुआ के अध्यक्ष घनश्याम भाटी ने बताया कि मप्र का आम नागरिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता तथा भाजपा युवा मोर्चा पद पर पदस्थ और सेन समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष, जमीनी स्तर से जुड़े हुए भाजपा के युवा निलेश विनोद परमार 'सेन', जो हर वर्ग को भाजपा की सरकार की योजनाओं से लाभान्वित करने का प्रयास करते है। वृहद स्तर पर होने वाले समाज का अन्नकूट आयोजन का भी पूर्ण लाभ लेते है। उनके लिए ''नर सेवा ही नारायण सेवा है''।

ऐसे झाबुआ जिले के ग्राम पारा में रहने वाले भाजपा से जुड़े युवा निलेश परमार को केश शिल्पी कल्याण बोर्ड का चेयरमेन नियुक्त किया जाना, ना केवल झाबुआ जिले अपितु संपूर्ण मप्र और भारत में भी समाज के लिए गौरव का विषय रहेगा। निलेश परमार इस पद पर रहकर समाज हित में ओर तत्परता तथा सक्रियता के साथ कार्य करेंगे। ज्ञापन में अंतः में कहा गया कि झाबुआ जिला, मप्र और संपूर्ण भारत कासर्व सेन समाज यह मांग रखता है कि निलेश परमार को शासन स्तर से इस पद पर जल्द ही मनोनीत कर गौरवान्वित किया जाए।

ज्ञापन की प्रतिलिपि सेन समाज की ओर से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा एवं स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग को भी प्रेषित की गई है। ज्ञापन सौंपते समय सेन समाज झाबुआ की ओर से राजेश देवड़ा, दिलीप सेन, संतोष परमार, विनोद सेन, प्रिया चौहान, रमेश सेन, मनोज सेन, कांतिलाल, कपिल सहित बड़ी संख्या में समाज के अन्य लोग उपस्थित थे।

11 दिसम्बर को जिला न्यायालय परिसर झाबुआ एवं तहसील न्यायालय पेटलावद एवं थांदला में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

माही की गूंज, झाबुआ।

11 दिसम्बर-2021 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ के द्वारा जिला न्यायालय परिसर झाबुआ एवं तहसील न्यायालय पेटलावद एवं थांदला में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन प्रधान जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ मोहम्मद सैयदुल अबरार के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। जिसकी तैयारी अपर जिला न्यायाधीश-सचिव लीलाधर सोलंकी के निर्देशन में की जा रही है। इसी तारतम्य में बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ द्वारा आगामी 11 दिसम्बर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए प्रचार वाहन को न्यायालय परिसर झाबुआ से प्रधान जिला न्यायाधीश मोहम्मद सैय्यदुल अबरार द्वारा हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। प्रधान जिला न्यायाधीश ने बताया कि इस वाहन के माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में लोगों को जानकारी तो होगी ही साथ ही विभाग के कार्यों के बारे में भी लोगों की समझ और बेहतर होती है। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार के लिए यह वाहन लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए सहायक होगा तथा जरूरतमंद एवं असक्षम लोगों को जागरूक करने का विशेष कार्य करेगा साथ ही यह प्रचार वाहन शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को विधिक जानकारी देगा ताकि अधिक से अधिक लोग लाभांवित हो सकें। इस प्रचार वाहन से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी पेम्पलेट का भी वितरण किया जायेगा। इस अवसर पर अपर जिला न्यायाधीश संजय चौहान, भरत कुमार व्यास, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नदीम खान, न्यायिक मजिस्ट्रेट राजकुमार चौहान, हर्ष ठाकुर, तनवी माहेश्वरी ठाकुर, प्रतिभा वास्कले, अमन सुलिया, अध्यक्ष अभिभाषक संघ झाबुआ दीपक भण्डारी, उपाध्यक्ष अर्चना राठौर, शरद चंद्र शुक्ला, राजेश कुमार पंड्या, सत्य प्रकाश पांचाल एवं अन्य अधिवक्तागण उपस्थित रहें।

दीक्षा समारोह सम्पन्न

माही की गूंज, थांदला।

दिगम्बर जैन समाज के गौरव दिगम्बर जैन तपस्वी संत महोत्सव सागरजी महाराज के 186 दिवसीय दीर्घ तपस्या का आज पारणा महोत्सव शिखरजी के पावन धाम मधुबन के मध्यलोक में करूणाणामूर्ति 108 आचार्य श्री पुण्यसागरजी महाराज के सानिध्य में मनाया गया। उनकी तप अनुमोदना में 108 आचार्य श्री विशुद्धसागरजी महाराज सहित करीब 70 मुनिराज शामिल हुए।

तपस्वी महोत्सव सागरजी महाराज के सिंहनिष्क्रीडित दीर्घ तपस्या के पारणा महोत्सव के दिन आचार्य श्री के मुखारविंद से ब्रम्हश्चारि सुशीला बाईजी (गोवहाटी), ब्रम्हश्चारि शकुंतला बाईजी (असम) व सौ. श्रीमती बबली देवी (मुंबई) ने आर्यिका दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा एवं पारणा महोत्सव में मध्यप्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मुंबई, दिल्ली, असम, गोवहाटी सहित अनेक प्रान्तों के करीब 5 हजार श्रद्धालु शामिल हुए। इस अवसर पर उपस्थित आचार्य श्री के साथ अन्य मुनिजन एवं आर्यिकाओं व थांदला दिगम्बर जैन संघ अध्यक्ष अरुण (बाला) कोठारी, उपाध्यक्ष पारस मेहता, कोषाध्यक्ष इन्द्रवर्धन मेहता, विजय भीमावत, पवन नाहर, प्रियंक मेहता, प्रकाश मेहता, चंद्रशेखर मेहता, राकेश मेहता, दीपक पिण्डरमा, रमेशचन्द्र मादावत, विशाल घोड़ावत, राहुल मेहता, सन्देश बोबड़ा, देवेंद्र मेहता, आनन्द मिंडा, संजय पिण्डरमा, अमित सालगिया, पप्पू मेहता, अनिल जैन झांसी वाले, पुष्पेंद्र मोदी, अंबर जैन, अनिल जैन, कीर्तिश मेहता, जीवंधर मेहता आदि ने तप अनुमोदना के साथ नव दीक्षितों के प्रति मंगल कामनाएं व्यक्त की। समारोह का सफल संचालन बाल ब्रमश्चारि वीणा दीदी (राजस्थान) ने किया।

नगरपालिका की सीमा मे आने वाले सभी प्रकार की संपत्तियों का जीआईएस आधारित सर्वे कार्य हुआ आरंभ

भोपाल के अधिकारियों ने नगरपालिका की टीम के साथ मिलकर वार्ड क्र. 18 से कार्य की शुरूआत की

माही की गूंज, झाबुआ।

मप्र शासन की योजना ''शहरी सुधार कार्यक्रम'' के हत नपा परिषद् झाबुआ की सीमा अंतर्गत आने वाले समस्त वार्डों में आने वाली शत-प्रतिशत आवासीय, व्यवसायिक एवं औद्योगिक संपत्तियों का जीआईएस (जियोग्राफिकल इंफारमेशन सिस्टम) आधारित सर्वे कार्य आरंभ हो चुका है। जिसकी शुरूआत मंगलवार शाम 4 बजे से नगरपालिका परिषद् के साथ भोपाल से आए अधिकारियों ने पायलेट वार्ड क्र. 18 से की।

वार्ड 18 के जीआईएस आधारित नक्शे का अवलोकन करते हुए नपाध्यक्ष, सीएमओ, पार्षद एवं भोपाल से आए अधिकारी।

वार्ड क्र. 18 में समस्त प्रकार की संपत्तियो का सीमांकन करते हुए भोपाल की टीम।

शुभारंभ अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष मन्नूबेन डोडियार, सीएमओ एलएस डोडिया के साथ राजस्व शाखा प्रभारी अयूब खान, सहायक मुकेश चौहान, वार्ड क्र. 18 के पार्षद नरेन्द्र राठौरिया तथा भोपाल से आए प्रोजेक्ट मेनेजर योगेश प्रतापसिंह और उनकी पूरी टीम भी मौजूद रहीं। जिसमें जीआईएस आधारित वार्डवार ड्रोन कैमरे से नक्शा तैयार करने के साथ प्रॉपटी (प्लाट) के अंतर्गत निर्मित सभी आरसीसी, टीनशेड, कच्चा पापर्टी, स्ट्रक्चर की भौतिक टेप द्वारा माप एवं प्रापटी-फेक्ट्री आदि का फोटोग्राफ लिया जाना है।

सागर एवं भोपाल की टीम को सर्वे की जिम्मेदारी सौंपी

उक्त कार्य के संपादन हेतु संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल मप्र द्वारा मेसर्स आभा सिस्टम एंड कंसल्टेंसी सागर के साथ संयुक्त उद्यम में मेसर्स मास्टर्स ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेस भोपाल को अधिकृत किया गया है। अनुबंधित संस्था की सर्वे टीम द्वारा नगरीय सीमा क्षेत्र में जीआईएस आधारित सर्वे कार्य शहर के 18 वार्डों में संचालित किया जाएगा। नगरपालिका द्वारा उक्त कार्य में संपूर्ण शहरवासियों से भी सहयोग की अपेक्षा व्यक्त की गई है। सर्वे कार्य से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नगरपालिका परिषद् झाबुआ में भी संपर्क किया जा सकता है।

अमानतदारो का सम्मान किया गया

माही की गूंज, झाबुआ।

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मया. झाबुआ के महाप्रबंधक आर.एस.वसुनिया के मार्गदर्षन मे बचत पखवाडा कार्यक्रम 8 दिसम्बर 2021 को मुख्य शाखा परिसर मे मनाया गया । इस अवसर पर कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्जवलित कर किया गया । कार्यक्रम के दोरान 07 वरिष्ठ अमानतदारो का शॉल, साफा एवं श्रीफल भेंटकर सम्मान किया गया ।

यह उल्लेखनीय है कि बैंक द्वारा समस्त शाखाओ मे दिनांक 1 दिसम्बर से 15 दिसम्बर तक बचत पखवाडा मनाया जा रहा है । जिसके अन्तर्गत बैंक की वित्तीय स्थिति को सुदृढ बनाने के लिये अमानतों पर ब्याज दरो मे वृद्धि की जाकर अधिक से अधिक अमानतों का संग्रहण किया जा सकें । जिसका व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है तथा इस दौरान अमानतदारो का भी सहयोग मिल रहा है । इस सप्ताह मे लगभग 50.00 लाख की अमानत प्राप्त की गई है ।

मुख्य शाखा के अमानतदार श्री कमलकांत मालवीय, पन्नालाल परमार, डॉ. लोकेन्द्रसिंह राठौर, कोकिला जैन, विरेन्द्र सकलेचा, अब्दूल वाहिद शेख एवं गौरव मांगीलाल का सम्मान किया गया ।

इस अवसर पर शाखा प्रबंधक दिलीप वाणी, सहायक लेखापाल राजेन्द्र माहेष्वरी, कु. आकांक्षा मगरे, राकेष कलेसिया, बल्लूसिंह वाखला आदि उपस्थित हुये । कार्यक्रम का संचालन श्रीमती सुषीला डामोर द्वारा किया गया।

जागो एसपी साहब...

चोरों ने एएसआई के घर किया हाथ साफ, एक रात में कई जगह चोरी को दिया अंजाम

क्या पुलिस करेगी एफआईआर दर्ज या आम जनता की तरह पुलिस को भी होना पड़ेगा प्रताड़ित

माही की गूंज, पेटलावद।

बीते एक माह में चोरो ने पेटलावद थाना क्षेत्र की पुलिस का जीना हराम कर दिया एक के बाद एक चोरी की घटना से पुलिस की नींदे उड़ी हुई है। इन चोरी की घटनाओं की खास बात ये है कि, चोर ग्रामीण इलाकों को नही, ज्यादातर उन्ही स्थानों को निशाना बना रहे है जहा पुलिस बल की पर्याप्त व्यवस्था है, मतलब चोर पेटलावद नगर सहित, बामनिया, सारंगी, करवड़ जैसे स्थानों पर रोज किसी न किसी तरह से बड़ी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। चोरो का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि, चोर एक रात में एक-दो नही दस-दस घरों को निशाना बना रहे है, वही पुलिस के पास अभी एक मात्र जवाब है कि, हम ट्रेस करने में लगे हैं। इस बार तो पुलिस के ही होश हव्वा हो गए, जब सारंगी चौकी के पीछे स्थित पुलिस लाइन में रहने वाले पुलिस स्टाफके निवास से चोरो ने लाखों का माल उड़ा लिया। रात में पेटलावद थाना अंतर्गत सारंगी चौकी एवं तहसीलदार निवास के पीछे बने पुलिस क्वार्टर पर अज्ञात चोरों ने दो पुलिसकर्मी के सुने घर का ताला तोड़कर पूरे घर का सामान साफकर दिया। पुलिसकर्मी अरुण गोयल के सूने घर से लगभग 5 लाख से अधिक सोने के जेवरात चोरी करने में कामयाब हो गए ,एवं सारंगी चौकी में पदस्थ नीरज हेड साहब के सूने घर पर भी निशाना बनाया गया ,जहां से उनका बैग वगेरा ले जाने में कामयाब हुए, हालांकि उनके घर में कोई नगदी एवं सोने-चांदी के जेवरात नहीं थे। जिसके कारण ज्यादा नुकसान नहीं हुआ ,वही सारंगी गांव में भी चोरों ने रात भर खूब उत्पात मचाया। सारंगी गांव में लगभग 4 से 5 घरों को निशाना बनाते हुए, चोरी का असफल प्रयास किया, क्षेत्र में लगातार बढ़ रही चोरी को पुलिस द्वारा ट्रेस नहीं कर पा रही है, जिससे स्थानीय पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। समय रहते पुलिस द्वारा चोरों को जल्द ट्रेस नहीं किया गया, तो क्षेत्र में बड़ी वारदातें एवं जनहानि होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अभी तो यह चोर सूने मकानों को निशाना बना रहे हैं लेकिन जिस प्रकार से चोर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। वो दिन दूर नही की वो खुले घरों में घुसकर भी मारपीट कर लूटपाट को अंजाम देगे। पेटलावद में हुई वकील मनोज पुरोहित के घर चोरी के मामले के बाद चोरो ने करवड़ में दो बार, बामनिया में और अब सारंगी में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है, बड़े मामलो को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर मामलों में पुलिस ने कोई मामला तक दर्ज नही किया है, ऐसे में पुलिस के घर हुई चोरी के मामले में पुलिस का क्या रुख रहता है ये देखना होगा।

दिन में सड़क पर पुलिस कर रही वाहनों की जांच , रात में गाड़िया चोरी

एक और पुलिस सुने घरों में चोरी की वारदातों से परेशान हैं तो दूसरी ओर बढ़ती वाहन चोरी की वारदातों ने पुलिस को परेशान कर रखा है, लगातार वाहन चोरी की वारदात भी बढ़ती जा रही है, मेला क्षेत्र से करडावद निवासी की एक और मोटरसाइकिल चोरी होंने की सूचना है। पेटलावद पुलिस दिन में बामनिया रोड, बदनावर रोड, थांदला रोड और रायपुरिया रोड पर सत्त वाहन चेकिंग अभियान चलाती है, जिसमे लगभग 10 से अधिक पुलिस, महिला आरक्षक सहित वाहन चेकिंग के नाम पर वसुली में व्यस्त रहते हैं। इतने समय मे इस अभियान में एक भी वाहन चोरी का पुलिस को जब्त करने में सफलता नही मिली, पुलिस द्वारा वाहनों को रोक कर केवल उनकी रसीद फाड़ कर रवाना कर दिए जाते हैं, जबकि लगातार बढ़ती वाहन चोरी की घटनाओं को देखते हुए रसीद बनाने और वसुली करने की जगह ये पुष्टि की जानी चाहिए कि, वाहन पर लिखा नम्बर यातायात विभाग में दर्ज है या नही ओर किसके नाम से दर्ज है जो कि डाटा आन लाइन भी उपलब्ध है, लेकिन पेटलावद पुलिस द्वारा वाहन जांच के नाम पर अघोषित वसूली की जा रही है ,बीते 15 दिनों में 5 से अधिक वाहन चोरी हो चुके है।

जागो एसपी साब

जिले में अपराध नियंत्रण करने का दावा करने वाले एसपी आशुतोष गुप्ता के सामने पेटलावद थाना क्षेत्र में लगातार हो रही वारदातो पर मौन धारण किये हुए है, आये दिन पुलिस व्यवस्था में बदलाव करने वाले साहब पेटलावद थाना क्षेत्र में बढ़ती वारदातों से निपटने के लिए यहां स्पेशल पुलिस को तैनात करना चाहिये, ताकि शराब के अवैध कारोबार से लेकर जुवे, सट्टे के कारोबार पर नियंत्रण कर चोरी की घटनाओं को ट्रेस कर सके। वही पुलिस का सूचना तंत्र पूरी तरह से धराशाई हो गया है, क्योकि किसी भी प्रकार की जानकारी पुलिस तक पहुँचने वालो के नाम बहार आ जाते हैं। जिससे सूचना देने वालो को आपसी रंजिश का शिकार होना पड़ता है जो अपराध ट्रेस नही होने का बड़ा कारण माना जा रहा है। बढ़ती चोरी की घटनाओं के चलते आम जन का पुलिस के खिलाफगुस्सा कभी भी फूट सकता है , वही कांग्रेस भी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर सरकार घेरने की तैयारी कर रही है।

शनिवार से शुरू हुई मंडी, मंगलवार को फिर से बंद

माही की गूंज, थांदला।

साप्ताहिक हाट (मंगलवार) जिस दिन क्षेत्र में सबसे ज्यादा आवक-व्यापार चलता है, उस दिन को छुट्टी के लिए चुना गया ताकि क्षेत्र का मंडी आधारित व्यवसाय मंडी से बाहर निजी दुकान पर ही संचालित किया जा सके एवं छुट्टी के नाम पर मंडी के बाहर कृषि व्यापार को सैद्धांतिक मंजूरी भी मिल जाए, जब कि होना यह चाहिए था की आज के दिन थांदला की मंडी व्यापार के पुराने सभी रिकॉर्ड को तोड़कर सर्वाधिक व्यवसाय करे, लेकिन यह हो ना सका। थांदला की मंडी को साप्ताहिक अवकाश के नाम पर मंगलवार को बंद रखा गया, लेकिन मंडी के बाहर व्यापार चालू रहा। ज्ञातव्य है कि, काफी प्रयासों के बाद थांदला मंडी को चालू किया जा सका है और मंडी की प्रसिद्धि हेतु इसे मंगलवार को चालू रखना अति आवश्यक एवं लाभकारी साबित हो सकता है। थांदला का कृषि व्यापार झाबुआ जिले में सबसे अहम स्थान रखता है, क्योंकि झाबुआ एवं अलीराजपुर जिले की सबसे बड़ी एवं मात्र दो कपास जीनिंग फैक्टरी थांदला एवं मेघनगर में है, जो कि थांदला मंडी के अधिकार क्षेत्र में आते है, मेघनगर में उपमंडी है यह भी थांदला मंडी के ही अधीनस्थ है, थांदला की सब्जी मंडी जो कि जिले की सबसे बड़ी मंडी भी है बिना किसी अवकाश के चलती है एवं सिर्फतीज त्यौहार पर बंद रखी जाती है, इसलिए मंगलवार के दिन अनाज मंडी को बंद रखना भी समझ से परे है, रविवार को मंडी कर्मचारी अवकाश पर रहते है यदि रविवार को थांदला मंडी को बंद कर क्षेत्र की एक उप मंडी काकनवानी को खोला जा सकता है, क्योंकि रविवार को काकनवानी का साप्ताहिक हाट बाजार लगता है, इस तरह यदि प्रयास किया जाए तो थांदला, काकनवानी, मेघनगर की तीनों मंडियों को एक साथ विकसित किया जा सकता है। थांदला मंडी परिसर में आज एकमात्र दुकान सूर्या ट्रेडर्स के द्वारा लगाई गई, बाकी सभी व्यापारियों द्वारा अपने नियत निजी व्यापार स्थल पर ही व्यवसाय किया गया। व्यापारियों के द्वारा असुविधा का हवाला दिया गया तो मंडी सचिव अश्विन वसावा का कहना है कि, आज मंडी में अवकाश होने से बाहर दुकान लगाई गई, जबकि मंडी प्रभारी अनिल भाना ने बताया कि, मंडी के विकास हेतु आवश्यक हुआ तो रविवार को अवकाश रखा जाएगा एवं मंगलवार को मंडी चालू रहेगी, लेकिन अब मंडी के बाहर कृषि व्यवसाय की अनुमति नहीं होगी।

बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 65 वां परिनिर्वाण दिवस मनाया गया

माही की गूंज ,पेटलावद।

बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 65वा परिनिर्वाण दिवस सोमवार को नगर के नई बस्ती में स्थित बाबा साहब की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर दीपोत्सव मनाया गया। जिसमें नगर परिषद अध्यक्ष मनोहर लाल भटेवरा, अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष जगदीश जाटव, समग्र अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष मनोज परमार, डॉ अंबेडकर राष्ट्रीय युवा संघ व बलाई समाज महासंघ के जिला अध्यक्ष मुकेश सिसोदिया, एवं पुरानी पेंशन बहाली महासंघ संयुक्त मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष नानूराम गामड़ सहित सुनील खोड़े, बबलू परमार, बलदेव सिंह राठौर, गोपाल परमार, रमेशचंद वाग, आदि भीम अनुयाई विशेष रूप से उपस्थित रहे, जिन्होंने बाबा साहब का पारिनिर्वाण दिवस मनाते हुए माल्यार्पण किया। वही भाजपा द्वारा सविंधान गौरव अभियान के अंतर्गत बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर उनकी प्रतिमा पर दीपोत्सव मनाया गया, जिसमे कार्यक्रम संयोजक एवं सहसंयोजक विशेष रूप से उपस्थित रहे।

माही की गूंज,थांदला।

जय संविधान कार्यक्रम संपन् लोकतंत्र के महापर्व ससंविधान गौरव दिवस के रूप में वागड़िया फलिया एमजी रोड अंबेडकर परिसर में बाबा साहेब की प्रतिमा पर अनुसूचित जाति मोर्चा थांदला मंडल द्वारा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मोर्चा के प्रदेश कार्यकारी सदस्य के जिला सह संयोजक राजू धानक विशेष अतिथि विजय नरवरिया, राजेश डामोर, सकल बलाई समाज ब्लॉक उपाध्यक्ष बल्लू लाल चौहान, मनीष वाघेला आदि कार्यकर्ताओं नै कैंडल प्रजलित कर बाबा साहेब अंबेडकर प्रतिमा पर पुष्प माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया कार्यक्रम को संबोधन राजू धानक ने भारत रत्न संविधान के जननायक, सर्वधर्म, सर्व ,समाज के जन कल्याणी संविधान की जो रोशनी हमको दी है वह घर घर शिक्षा को महत्व देने आत्म निर्भर बनने की बात कहीं कार्यक्रम सविधान गौरव दिवस संपन्न हुआ कार्यक्रम का सफल संचालन प्रफुल्ल धामनिया ने किया, आभार शोमेस डामेसा माना।

सात सालों के लंबे अंतराल के बाद भी नहीं बन पाया आदर्श गांव

माही की गूंज, थांदला।

परवलिया नाम से ही चरितार्थ है परवलिया याने कि दूसरों पर मेहरबान होने वाला, आगंतुकों और मेहमानों के साथ उच्च व्यवहार एवं प्रगति के लिए बना गांव। भगवान रणछोड़ राय की कृपा दृष्टि एवं उगमणी तथा आथमणि नामक दो नदियों के बीच बसा परवलिया समस्त प्राकृतिक संभावनाओं के बावजूद भी अपने विकास की बाट जोह रहा है। आस-पास की पंचायतों मसलन, मानपुर, चिकलिया, रूपगढ़, आमली, दौलतपुरा, खांदन, टिमरवानी के साथ ही देवीगढ़, झापादरा एवं इटावा का यह मुख्य संपर्क एवं व्यापारिक केंद्र है, मसलन यही से इनकी फसल, इलाज, शासकीय सुविधा, बैंकिंग जरूरतों की पूर्ति होती है। सुविधाओं के नाम पर अब से 20 वर्षों पूर्व और आज के परवलिया की बात करें तो शायद गांव के रहवासी पुराने दिनों की शासकीय व्यवस्था को आज से लाख गुना बेहतर ही मानेंगे, आज से लगभग दो दशक पूर्व परवलिया में पोस्ट-ऑफिस, पंचायत भवन, पुलिस-चौकी, ग्राम विकास अधिकारी, बैंक, शासकीय अस्पताल डॉक्टर के साथ, पानी की टंकी, गांव की प्रत्येक गली में हैंडपंप की व्यवस्था, शासकीय स्कूल की उच्च गुणवत्ता वाली पढ़ाई एवं खेल की सुविधा, बालक एवं बालिका छात्रावास, पशुओं के लिए अस्पताल, कांजी हाउस, दूध डेयरी, मंदिर, दरगाह, नदी का घाट, स्टाप डेम, भरपूर पानी आदि इन सभी सुविधाओं के साथ परवलिया क्षेत्र का सबसे समृद्ध गांव था, लेकिन शासकीय उदासीनता, मजबूर राजनैतिक इच्छा शक्ति के अभाव एवं भ्रष्ट आचरण के चलते आज गांव की यह दशा हो चुकी है कि, पीने के पानी जैसी मूलभूत आवश्यकता के लिए लोगों को रोज सुबह 1-2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, सिर पर एवं मोटर साईकिल पर पानी के खाली - भरे केन लिए लोग सुबह बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। लगभग 30,000 की आबादी परवलिया के आस-पास लगभग 8 पंचायतों में निवास करती है लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर एक पूर्ण विकसित स्वास्थ्य केंद्र या डाक्टर की सुविधा आज तक नहीं मिली, पानी की टंकिया बनी लेकिन आज तक उपयोग में नहीं लाई गई, पुराना पंचायत भवन आज भी ग्राम विकास की बाट जोह रहा है, दूध डेयरी एवं कांजी हाउस की सुविधा भी दम तोड़ चुकी है। गांव में ना तो पोस्ट - ऑफिस की सुविधा है और ना ही कभी किसी कृषि एव ग्राम विकास से संबंधित अधिकारियों को ग्राम में निवास की अपील की, स्कूल, पंचायत या फिर किसी भी शासकीय विभाग का कोई कर्मचारी यहां निवास करता है, खेल के मैदान, गौशाला या फिर चारागाह की कोई सुविधा का प्रयास ही नहीं हुआ, सामुदायिक भवन का निर्माण भी अनदेखी के अभाव में पूर्णता से पहले ही बिखरना शुरू हो गया, सिंचाई के लिए ना कोई तालाब बने ना ही नदी पर कोई व्यवस्था की गई, मंडी या फिर बाजार लगवाने या हाट एवं व्यापार मेले की बात ही बेमानी लगती है, शासकीय कुओं एवं नलकूपों को भी निजी हाथों में सौंप दिया जाना गांव के जलसंकट को भी जन्म दे गया, आखिर इन सबके बावजूद भी किसी तरह कुशल हिसाब-किताब का तमगा मिला और बदले में 12 लाख की बड़ी धनराशि एवं आदर्श ग्राम की संकल्पना मिली, लेकिन साकार रूप में कहा परिकल्पित हुई यह ढूंढ पाना मुश्किल ही लगता है...? खैर अब फिर से एक मौका चुनाव आयोग ने दे दिया है, आगामी 28जनवरी को परवलिया का प्रथम नागरिक बनने का सौभाग्य किसे मिलता है? एवं परवलिया का तारणहार बनाने का भार गांव की जनता किसे सौंपती है यह अब परवलिया के ग्राम वासियों एवं उनकी समझ शीलता पर निर्भर करेगा, सभी को ग्राम विकास के सबसे बड़े त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं।

उच्च शिक्षा मंत्री के नाम दिया ज्ञापन

माही की गूंज,थांदला।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई थांदला ने कार्यकर्ता व छात्रों द्वारा उच्च शिक्षा मंत्री मध्यप्रदेश शासन भोपाल के नाम पर शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा ज्ञापन में मांग की गई,छात्रवृत्ति व आवास सहायता राशि का भुगतान करें। नए सत्र 2021-22 में छात्रवृत्ति फार्म भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करें क्योंकि जनजाति बहुल जिला होने से छात्रवृत्ति व मजदूरी पर छात्रों की पढ़ाई निर्भर रहती है। महाविद्यालय के छात्रों को काफी स्टेशनरी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, महाविद्यालय प्रशासन और शासन सभी छात्रों को समान दृष्टि से देखते हुए उक्त मांगों का शीघ्र समाधान करें अन्यथा छात्र शक्ति विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगी जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन सरकार की रहेगी। ज्ञापन में जिला संयोजक प्रताप कटारा अध्यक्ष विकास भूरिया एवं परिषद के पदाधिकारी व छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

रेत के अवैध परिवहन पर सतत् कार्यवाही जारी

माही की गूंज, झाबुआ।

रेत के अवैध परिवहन पर सतत् कार्यवाही की जा रही है। कलेक्टर सोमेश मिश्रा द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन में राजस्व अमले तहसीलदार सुखदेव डावर एवं खनिज अमले द्वारा मंगलवार को राणापुर में सघन चैकिंग अभियान चलाया गया। जिसमें डम्पर क्रमांक जी.जे.-19-8288 व 2 टेउक्टर ट्राली बिना नंबर की अवैध रेत परिवहन करते पाए जाने पर थाना राणापुर की अभिरक्षा में रखे गए। इन सभी वाहनों पर म.प्र. रेत (खनन, परिवहन तथा भण्डाकरण एवं व्यापार) नियम 2019 के अंतर्गत अर्थदण्ड वसूल किए जाने की कार्यवाही की जाएगी।

सभ्य नागरिक ने बेतरतीब वाहन पार्किंग को लेकर थांदला पुलिस से की थी शिकायत

बयान के वक्त दिखाया पुलिसिया रौब

तिवारी की टेंगरई लगा रही पुलिस की देश भक्ति जनसेवा वाली छवि पर दाग

माही की गूंज, थांदला।

देश जहां स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। तो वहीं सरकार व राजनीतिक दल के पदाधिकारी, नेता आदि आजादी के महायज्ञ में आहुतियां डालने वाले वीरों के घर जाकर अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे है। तो वहीं थांदला पुलिस का एक एसआई अपने पुलिसिया दंभ में इतना मदहोश है कि उसे सभ्य नागरिक व स्वतंत्रता सेनानी परिवार के उत्तराधिकारी से बात करने की तमीज भी नहीं है। उस सभ्य नागरिक का दोष केवल इतना था कि उसने बेतरतीब वाहन पार्किंग को लेकर थाना प्रभारी को एक पत्र लिखा था। उस पर 40 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने पर पुलिस अधीक्षक को इस मामले से अवगत करवाया गया। जिस पर थांदला थाने पर बयान के लिए बुलाने पर जमकर अभद्रता की गई। जिला पुलिस अधीक्षक को इस संबंध में पत्र लिखने वाले को बयान देने के लिए पुलिस थाने पर बुलाया गया। उसके साथ अपराधी जैसा व्यवहार कर उसे अपमानित करते हुए पुलिसिया लहजे में कहा गया- यह पुलिस थाना है, समझे। आप बाहर कुछ भी हो, हमें कोई लेना देना नहीं। ज्यादा मत बोलना, जितना पूछे उतना उत्तर देना।

हुआ यूं कि एक कपड़ा व्यापारी और उसके यहां काम करने वाले नौकरों के 8-10 वाहन पिछले 2 वर्ष से अधिक समय से जिस व्यक्ति के मकान के सामने रखते हुए उसे जगह को स्थानी वाहन स्टैण्ड बना लिया। चोरी और सीना जोरी की कहावत को चरितार्थ करते हुए झगड़े की स्थिति निर्मित कर दी।

इसी बात को लेकर सभ्य नागरिक व 45 वर्षों से राज्य स्तरीय पत्रकारिता की सूची में शामिल मकान मालिक ने पुलिस थाना प्रभारी को 27 सितबंर को पत्र भेजा था। जिस पर 40 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं होने पर 5 नवंबर को पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजा तब कही जाकर 20 नवंबर को स्थानी वाहन स्टैंड हटाने की कार्रवाई हुई।

इस सभ्य नागरिक ने बताया कि , 27 नवंबर को पुलिस थाना थांदला में संबंधित व्यक्ति को बयान देने के लिए बुलाया गया। एसआई तिवारी ने कहा- यह पुलिस थाना है। आप बाहर कोई भी मुझे कोई लेना देना नहीं है, जितना पूछा जाए उतना उत्तर देना। फालतू दिमाग खराब मत करो, मेरे पास टाइम नहीं है।

एसआई तिवारी बार-बार यह दोहराते रहे, जिस पर जिन्हें बयान देने के लिए बुलाया था उन्होंने कहा कि आप बोलने नहीं दे रहे हैं, मैं कुछ बोल भी नहीं रहा हूं। सुन लीजिए मैं कुछ भी नहीं- मैं तो स्वतंत्र भारत का साधारण नागरिक हूं।

इस पर एसआई तिवारी ने कहा कि चुप रहो यह पुलिस थाना है। उन्होंने दो लाइन का बयान लिखा- पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट हूं, आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहता। तिवारी ने कहा हस्ताक्षर करो और चुपचाप चलते बनो।

अब आप ही फैसला कीजिए कि यह व्यक्ति नगर का सम्मानीय होकर प्रदेश व देश में सम्मानित है। ऐसे व्यक्ति के साथ पुलिस थाने में एक अपराधी-सा व्यवहार शोभा देता है। जांचकर्ता एसआई तिवारी की यह टेंगरई क्या पुलिस की देश भक्ति जनसेवा वाली छवि से मेल खाती है। जब एक सम्मानित नागरिक के साथ पुलिसिया बर्ताव ऐसा है तो आम लोगों के साथ पुलिस का रवैया कभी सम्माजनक हो सकता है।

एक तरफ मप्र के गृहमंत्री सामाजिक पुलिसिंग के साथ पुलिस की छवि को सुधारने की बात करते हैं तो क्या पुलिस के ऐसे रवैये से उनकी छवि को चार चांद लग पाएंगे।

उस सभ्य व्यक्ति का कहना है कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कार्यवाही के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। साथ ही आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पुलिस थाना थांदला के एसआई तिवारी ने जो व्यवहार किया है उसके लिए उनके पास कोई शब्द नहीं है।

संपादकीय

दोस्तीः रणनीतिक संतुलन के लिए जरूरी रूसी मैत्री

यूक्रेन विवाद और कोरोना चुनौती के बीच रूसी राष्ट्रपति का भारत आना निःसंदेह इस बात का प्रतीक है कि, पुतिन भारत से संबंधों को अपनी प्राथमिकता देते हैं। इस यात्रा के गहरे निहितार्थ हैं सामरिक दृष्टि से और कारोबारी रिश्तों की वजह से भी। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत रूस से उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एस-400 खरीद रहा है, जिस पर अमेरिका की भौंहें तनी हुई हैं। अमेरिका ने नाटो संगठन के देश तुर्की पर रूस से

ऐसी ही मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली खरीदने पर प्रतिबंध लगाये थे। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को संदेश दिया है कि, भले ही कई मामलों में भारत का अमेरिका के प्रति झुकाव रहा हो, लेकिन अपने रणनीतिक हितों के लिए विदेश नीति निर्धारण में वह किसी देश का पिछलग्गू नहीं है। भारत-रूस के इस 21वें शिखर सम्मेलन में पुतिन व मोदी की बातचीत के अलावा 'टू प्लस टू' बैठकों में दोनों देशों के रक्षा व विदेश मंत्रियों की मुलाकातें महत्वपूर्ण होते रिश्तों की बानगी दर्शाती है। इस दौरान हुए महत्वपूर्ण समझौते इस बात पर मोहर लगाते हैं। निःसंदेह, रूस भारत का भरोसेमंद सहयोगी रहा है और संकट के कई मौके पर हमारे साथ खड़ा रहा है। यही वजह है कि दोनों देशों में रक्षा सहयोग दस वर्ष बढ़ाने पर सहमति बनी है। इस वार्ता में दोनों देशों के नेताओं की गर्मजोशी प्रगाढ़ होते रिश्तों को दर्शाती है। निःसंदेह, पुतिन कुछ ही घंटों के लिये भारत आए, लेकिन इस यात्रा के महत्वपूर्ण मायने हैं। खासकर ऐसे समय में जब साम्राज्यवादी चीन लगातार सीमा पर भारत के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है और अफ़ग़ानिस्तान में पाक-परस्त तालिबान सत्ता में काबिज हो गया है, भू-सामरिक दृष्टि से रूसी राष्ट्रपति की भारत यात्रा और महत्वपूर्ण हो जाती है। शांति, सहयोग व दोस्ती के पांच दशक व रणनीतिक साझेदारी के दो दशक पूरा होना, दोनों देशों के भरोसे के रिश्तों को ही दर्शाता है। कोविड संकट के दौरान जब देश दूसरी लहर से जूझ रहा था और पश्चिमी देशों द्वारा वैक्सीन निर्माण से जुड़ी सामग्री देने में आनाकानी की जा रही थी, तब रूस आगे आया और भारत के लिये स्पूतनिक वैक्सीन की आपूर्ति और उत्पादन पर सहमति बनी थी।

दरअसल, पुतिन की इस यात्रा के दौरान भारत व रूस सामरिक व रक्षा चुनौतियों के बाबत ही साथ खड़े नजर नहीं आए, बल्कि आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी व संगठित अपराधों से जूझने में साझा लड़ाई की बात कही गई। इन मुद्दों में पुतिन द्वारा भरोसा देना पाक को भी सख्त संदेश है, जो सीमापार से भारत के खिलाफ आतंकवाद व नशीले पदार्थों की तस्करी को हथियार की तरह इस्तेमाल करता रहा है। वहीं पुतिन ने भारत की सीमा पर चीन के जमावड़े पर चर्चा करते हुए स्पष्ट कहा कि भारत एक बड़ी ताकत है। बहरहाल, अब तक रक्षा व अंतरिक्ष विषयों पर सहभागिता करने वाले भारत व रूस ने टू-प्लस-टू बैठक में इन्हें विस्तार देने पर सहमति व्यक्त की है। दूसरी ओर सेना को आधुनिक हथियार मुहैया कराने के क्रम में अत्याधुनिक असॉल्ट राइफल एके-203 की खरीद तथा अमेठी में आयुध फैक्टरी में लाखों राइफलों के निर्माण का समझौता हथियार बनाने में भारत की आत्मनिर्भता की दिशा में एक बड़ा कदम कहा जा सकता है। विश्वास है कि, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और कीमतें तय करने की अड़चनों को दूर करने के बाद अब इनका निर्माण गति पकड़ेगा। साथ ही क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी। वहीं क्लाशनिकोव शृंखला के छोटे हथियारों के उत्पादन के बारे में वर्ष 2019 के समझौते में संशोधन व सैन्य एवं तकनीकी सहयोग के क्षेत्र में अंतर को सरकारी आयोग के प्रोटोकॉल में बदलाव किया गया है। निस्संदेह, दोनों देशों के भरोसेमंद रिश्तों को पुतिन की यात्रा से और मजबूती मिलेगी। खासकर अचूक मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली एस-400 की आपूर्ति शुरू होने से पड़ोसी मुल्क भारत पर हमले की कोशिश से पहले कई बार विचार करेंगे। भारत ने इसे अपनी रणनीतिक संप्रभुता के लिये अपरिहार्य बताया है, जिसके चलते अमेरिका व चीन की निगाहें पुतिन की भारत यात्रा पर लगी थी।

रोजगार व संप्रभुता हेतु संरक्षणवाद जरूरी

बीते वर्ष में अपने निर्यातों में 10 अरब डालर की वृद्धि हुई है तो आयातों में 21 अरब डालर की। सच यह है कि, निर्यात बढ़ाने के प्रयास में हमारे आयात बढ़ रहे हैं और हम दबते जा रहे हैं। सरकार ने पिछले वर्ष इस समस्या का संज्ञान लेते हुए चीन के की एप जैसे जूम और कैम स्कैनर पर और रक्षा से सम्बन्धित लगभग 100 वस्तुओं पर प्रतिबन्ध लगाया था। कोट, पैंट, ज्यूलरी, प्लास्टिक, केमिकल, चमड़ा इत्यादि पर आयात कर बढ़ाए थे। लेकिन ये कदम पर्याप्त सिद्ध नहीं हुए हैं। हमारे आयात दिनोंदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। कारण यह है कि हमने खुले व्यापार को अपना रखा है।

अर्थव्यवस्था को चलाने के दो माडल हैं। एक यह कि, हम खुले व्यापार को अपनाएं और अपने माल का निर्यात करने का प्रयास करें। विदेशी माल आयात करने की छूट दें ताकि हमारे निर्यात क्षेत्र में रोजगार उत्पन्न हो सके और हमारे उपभोक्ता को सस्ता विदेशी माल उपलब्ध हो। इस माडल की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम कितना निर्यात कर पाते हैं। सस्ते आयातों का पेमेंट करने के लिए निर्यात से डॉलर अर्जित करना जरूरी होता है। पिछले वर्ष का अनुभव प्रमाणित करता है कि, खुले व्यापार के माडल से हमें सफलता नहीं मिल रही है। निर्यातों में वृद्धि कम और आयातों में वृद्धि अधिक हो रही है। इसलिए हमें दूसरे संरक्षणवाद के माडल को अपनाना चाहिए।

इस माडल में हम केवल अति जरूरी माल के आयात को छूट देते हैं। शेष माल पर भारी आयात कर लगा देते हैं, जिससे कि अधिकाधिक माल का उत्पादन अपने देश में हो। संरक्षणवाद का लाभ यह है कि हम अधिकतर माल में आत्मनिर्भर हो जाते हैं। हमारी आर्थिक संप्रभुता की रक्षा होती है। नुकसान यह है कि, हमें विदेशों में बना सस्ता माल नहीं मिलता। दूसरा नुकसान है कि हमारे उद्यमी अकुशल उत्पादन में लिप्त हो जाते हैं। विदेशी माल पर आयात कर अधिक होने से आयातित माल महंगा पड़ता है और हमारे उद्यमी मुनाफाखोरी करते हैं या अकुशल उत्पादन करते हैं क्योंकि उन्हें सस्ते विदेशी माल से प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत नहीं रह जाती। इस तथ्य के बावजूद हमें संरक्षणवाद को अपनाना चाहिए।

मान लें कि, संरक्षणवाद को अपनाने से अपने देश में अकुशल उत्पादन होता है तो भी इस अकुशल उत्पादन में हमारे श्रमिकों को रोजगार मिलता ही है। उनकी क्रय शक्ति में वृद्धि होती है। अतः प्रश्न यह है कि, हम अपने श्रमिकों को रोजगार के साथ महंगा घरेलू माल परोसेंगे या बेरोजगारी के साथ सस्ता विदेशी माल? यदि हम खुले व्यापार को अपनाते हैं और सस्ता विदेशी माल अपने देश में आता है तो हमारे उद्योग बंद हो जाते हैं। हमारे श्रमिक बेरोजगार हो जाते हैं। विदेश का बना सस्ता माल हमारी दुकानों में उपलब्ध तो होता है लेकिन श्रमिक की जेब में नकद नहीं होता कि वह उस माल को खरीद सके। सस्ता माल उपलब्ध कराकर

उन्हें बेरोजगारी के साथ भुखमरी की कगार पर लाने की तुलना में रोजगार के साथ महंगा माल उपलब्ध कराना उत्तम है। तब माल कम भी मिलेगा तो भी वे कुछ खपत तो कर ही सकेंगे। भूखे नहीं मरेंगे।

खुले व्यापार का सिद्धांत है कि, हर देश उस माल का उत्पादन करेगा जिसे वह कुशलतापूर्वक बना सकता है। जैसे भारत गलीचे का कुशल उत्पादन करे और चीन बिजली के बल्ब का कुशल उत्पादन करे। भारत सस्ते गलीचों का निर्यात करे और चीन सस्ते बल्ब का निर्यात करे। तब भारत में गलीचे के उत्पादन में रोजगार बनेंगे और उस आय से भारतीय नागरिक चीन के सस्ते बल्ब को खरीद सकेंगे। इसी प्रकार चीन के नागरिक को बल्ब के उत्पादन में रोजगार मिलेंगे और उस आय से वे भारत में बने सस्ते गलीचे को खरीद सकेंगे।

यह सिद्धांत सही है लेकिन यह गैर आवश्यक माल मात्र पर लागू होता है। जैसे मान लीजिये हम स्टील का आयात चीन से करने लगें तब हम अपने देश में बंदूक, पनडुब्बियां, हवाई जहाज इत्यादि का उत्पादन भी नहीं कर सकेंगे क्योंकि इनके उत्पादन के लिए हमें स्टील चाहिए, जिसे प्राप्त करने के लिए हम चीन पर आश्रित हो जायेंगे। इसलिए अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए जरूरी है कि हम आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन अपने देश में ही करें, यह चाहे महंगा ही क्यों न पड़े। जैसे यदि देश में उत्पादित स्टील का दाम 50 रुपए प्रति किलो है और विदेश में उत्पादित स्टील का दाम 40 रुपए प्रति किलो है तो हम विदेशी स्टील पर 10 रुपए का संप्रभुता अधिभार लगा सकते हैं। चूंकि हमारे लिए अपने ही देश में स्टील का उत्पादन करना आवश्यक है। तब अपने देश में बने स्टील और आयातित स्टील दोनों का दाम 50 रुपये प्रति किलो हो जाएगा और अपने देश में स्टील का उत्पादन हो सकेगा। फिर हम चीन पर आश्रित नहीं होंगे।

डॉ. भरत झुनझुनवाला
आर्थिक विशलेषक

संरक्षणवाद के विरोध में तर्क 1950 से 1990 की हमारी दुर्गति का दिया जाता है। यह सही है कि उस समय हमने संरक्षणवाद को अपनाया और और अपना देश वांछित प्रगति नहीं कर सका लेकिन इसका कारण केवल संरक्षणवाद को ही नहीं ठहराया जा सकता है। सही बात यह है कि यदि हम संरक्षणवाद के साथ अपने घरेलू उद्यमियों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन दें तो आपसी प्रतिस्पर्धा में ये स्वयं कुशल उत्पादन करने लगेंगे। फिर उद्यमी कुशल भी हो जायेंगे और हम निर्यातों का सामना भी कर सकेंगे।

आश्चर्य की बात है कि, इस तथ्य को हमारे सरकारी अधिकारी क्यों नहीं समझते? अधिकांश अधिकारियों और नेताओं के संतानें बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में कार्य करती हैं। सेवानिवृत्ति के बाद ये स्वयं विश्व बैंक की सलाहकारी करने को उत्सुक रहते हैं। इसलिए इनकी मानसिकता ही बन जाती है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हितों को साधें और वे अनजाने में ही देश हित की ऐसी गलत परिभाषा कर बैठते हैं जिसके अंतर्गत हम आयातों पर निर्भर होते जा रहे हैं और हमारे नागरिक बेरोजगार होते जा रहे हैं।

ममता के मन में क्या?

किसी समय यूपीए का हिस्सा रह चुकीं ममता बनर्जी अब साफसंकेत दे रही हैं कि, वे न तो स्वयं कांग्रेस का नेतृत्व मंजूर करेंगी और बल्कि दूसरी पार्टियों को भी कांग्रेस की तरफ जाने से रोकने के लिए अपना हरसंभव प्रयास करेंगी। जानकार कहते हैं, इसलिए ममता ने यूपीए के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिया है ताकि क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस से छिटक कर उनकी तरफ आ जाएं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने एनसीपी नेता शरद पवार से मिलने के बाद कहा कांग्रेस नेतृत्व वाला यूपीए (यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलायंस) गठबंधन अब कहां है। यह खत्म हो चुका है। उससे पहले ममता बनर्जी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन पर तंज कसते हुए कहा 'कुछ ऐसी पार्टियां और लोग हैं जो कुछ नहीं करते हैं। आधा समय तो वो विदेश में गुजारते हैं। हालांकि कांग्रेस उनके इस बयान पर हमलावर हो गई है और कहा है कि कांग्रेस के बिना भाजपा का मुकाबला नहीं किया जा सकता। यूपीए को लेकर दिया ममता बनर्जी का यह बयान इसलिए अहम है क्योंकि ममता बनर्जी खुद को विपक्ष के नेता के तौर पेश कर रही हैं और दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों को इसके लिए लामबंद कर रही हैं। ममता की मुंबई यात्रा और शिवसेना और एनसीपी नेताओं से उनकी मुलाकात इसी रणनीति का एक हिस्सा है। राजनीति के जानकार यह कहते हैं कि, ममता अपनी सियासी पटकथा इस तरह लिख रही हैं कि वे कांग्रेस को पूरी तरह किनारा करके कांग्रेस का विकल्प बनना चाहती हैं। वे बार-बार इस बात पर जोर दे रही हैं कि, कांग्रेस भाजपा को चुनौती देने की स्थिति में नहीं है इसलिए क्षेत्रीय ताकतों के लिए वे ही एक विकल्प हैं। ममता बनर्जी अपने सियासी करियर के सबसे कठिन चुनावों में से एक को जीतने के बाद सबसे मजबूत विपक्षी चेहरे के रूप में उभरी हैं। ऐसे में उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में

एक बड़ी भूमिका निभाने के तौर पर भी देखा जा रहा है। मिशन 2024 के तहत ममता की नजर पीएम की कुर्सी पर तो है लेकिन, ये यह बात भी उन्हें पता है कि कांग्रेस को किनारे रखते हुए आम सहमति बना पाना टेढ़ी खीर है। ममता साफसंदेश दे रही हैं कि अभी अगर विपक्ष एकजुट नहीं हुआ तो फिर भाजपा का मुकाबला करना आसान नहीं होगा। हालांकि, ममता से जब सवाल किया गया कि 2024 में विपक्ष का नेता कौन होगा तो उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया। इतना ही कहा, मैं ज्योतिषी नहीं हूं। इससे जाहिर होता है कि, विपक्षी एकता का चेहरे को लेकर कशमकश बना हुआ है। ममता के फॉर्मूले को सोनिया गांधी स्वीकार करती हैं तो कांग्रेस क्षेत्रीय दलों की मर्जी पर निर्भर रहेगी। ऐसे में सवाल उठता है कि कांग्रेस अगर इस फॉर्मूले को मान भी लेती है तो उसे सियासी तौर पर फायदा क्या होगा। कांग्रेस अगर लोकसभा चुनाव में क्षेत्रीय दलों की जूनियर पार्टनर की तरह रही तो उसके रिवाइवल की

सिद्धार्थ शंकर

उम्मीदें हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। कांग्रेस अपने भविष्य को लेकर ये जोखिम मोल लेगी ऐसा लगता नहीं है। दरअसल कांग्रेस भी इन्हीं क्षत्रपों को 2024 में एकजुट करके मोदी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरने की कवायद कर रही है लेकिन कांग्रेस जूनियर पार्टनर के तौर पर नहीं बल्कि गठबंधन के सबसे मजबूत दल के रूप में इसकी अगुवाई करना चाहती है। ऐसे में कांग्रेस के मंसूबों से उलटा ममता का फॉर्मूला है। जाहिर है कांग्रेस के लिए इसे स्वीकारना आसान नहीं होगा। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी भी विपक्ष का चेहरा बनने के लिए सक्रिय हैं। संसद में मोदी सरकार को घेरने के लिए पिछले दिनों में वह विपक्षी दलों की बैठक कर संसद में घेरते नजर आए हैं। हालांकि, विपक्षी दलों के नेताओं का भरोसा राहुल गांधी अभी तक जीत नहीं पाए हैं। वहीं, ममता को बतौर चेहरा पेश करने को लेकर क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर कई अड़चनें हैं। क्षेत्रीय स्तर पर कई दलों के समक्ष एकसाथ खड़े होने की समस्या है, जैसे उत्तर प्रदेश में सपा-बसपा एक साथ खड़े नहीं हो सकते। पश्चिम बंगाल में वाममंथी ममता के पीछे खड़े नहीं हो सकते। दिल्ली में कांग्रेस और आप का एक साथ नहीं है। पंजाब में भी हालत ऐसी ही बनी हुई है।

तूफानों की स्पांसरशिप का उम्मीदभरा बाजार

जवाद तूफान का नाम है, जवाद का अरबी भाषा में मतलब होता है, दयालु उदार। तूफान भी उदार हो सकते हैं, नेता भी कम ठग हो सकते हैं, हत्यारे भी कम क्रूर हो सकते हैं। नाम में क्या रखा है-यूं शेक्सपीयर कह गये हैं, तूफान तूफान होता है। उसे उदार कह देने भर से वह उदार न हो जाता। हाल में चेन स्नैचिंग में धरे गये एक युवक नाम था-परहित प्रसाद-दूसरों के हित में कार्यरत।

तूफानों के नामों से भी कमाई का जुगाड़ हो सकता है, एमबीए में अध्ययनरत एक बालक ने अपने प्रोजेक्ट का शीर्षक यूं रखा-तूफानों की स्पांसरशिप। उस प्रोजेक्ट के मुख्य अंश, हर जगह से कमाना चाहिए, तूफानों से भी कमाने की युक्ति संभव है। तूफान का नाम जवाद रखा गया, पहले आये एक तूफान का नाम हुदहुद रखा गया, अमेरिका के एक तूफान का नाम कैटरीना रखा गया। नाम में बहुत कुछ रखा है, नाम के लिए बंदा कई ऐसे काम करने को तैयार हो जाता है, जो

उसे बदनाम तक कर सकते हैं, पर बदनाम होंगे, तो भी नाम होगा, तो ऐसे बदनामी-प्रुफलोगों के लिए एक स्कीम लांच की जा सकती है कि जो भी अधिकतम भुगतान करेगा, तूफान का नाम उस पर रख दिया जायेगा। गौर से देखिये, बड़े-बड़े चोर ठग पर बहुत अमीर टाइप के कारोबारियों के निधन के बाद उनकी जो श्रद्धांजलि छपती है, उसमें उन्हें परोपकारी, महामानव टाइप घोषित किया जाता है। जिसकी जेब में रकम में नहीं है, वह ईमानदार बंदा बतौर मानव भी मुश्किल से जी पाता है। तो हमें तूफानों के नाम की स्पांसरशिप बेच देनी चाहिए। जैसे ही पता चले कोई और तूफान आने वाला है, वैसे ही फौरन नामों की नीलामी कर देनी चाहिए। टंटोमल या घंटोमल जो भी रकम दे, चकाचक, तूफान का नामकरण उसके नाम पर ही कर देना चाहिए।

कटारमल या जटारमल जो ज्यादा रकम दे, तूफान उसके नाम कर दो। इससे बहुत रकम जुटायी जा सकेगी, और उस रकम के एक अंश का इस्तेमाल तूफान से प्रभावित लोगों को राहत देने में भी किया जा सकता है। तूफानी तेजी वाला कोल्ड ड्रिंक भी किसी तूफान को स्पांसर कर सकता है। बाद में दावे प्रतिदावे भी हो सकते हैं कि हमारे वाला तूफान ज्यादा मारदार और धारदार था, तो कुल मिलाकर अधिकतम रकम तूफानों के स्पांसरों से खींची जा सकती है। कोई चाय कंपनी भी तूफान को स्पांसर करने में रुचि दिखा सकती है, तूफान ताजगी मिलती है उस चाय से, इसी चाय ने फलां तूफान स्पांसर किया था।

आलोक पुराणिक

संभव है कि, कमाई बढ़ाने के लिए कुछ फर्जी टाइप के तूफान खड़े कर दिये जायें। कुछ टीवी एंकरों की मदद से नकली तूफान खड़े किये जा सकते हैं, टीवी एंकरों को नकली तूफान खड़े करने में परम महारथ हासिल है। फिर तूफानों को बेचना आसान हो जायेगा।

राजनीतिक दलों की जवाबदेही सुनिश्चित हो

लोकतांत्रिक प्रणाली को अपराधीकरण से मुक्त कराने के न्यायपालिका के प्रयासों को मिली सफलता के बीच अब सजायाफ्ता नेताओं पर आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने की मांग जोर पकड़ रही है। न्यायालय भी सरकार से जानना चाहता है कि क्या वह सजायाफ्ता नेताओं के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाना चाहती है।

एक आम धारणा है कि, अदालत द्वारा दोषी ठहराये गए नेताओं के चुनाव लड़ने पर अगर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया जाए तो इससे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था आपराधिक तत्वों से पूरी तरह से मुक्त हो सकती है। लेकिन फिलहाल कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए इस बारे में कानून बनाने की आवश्यकता होगी, जिसके लिए राजनीतिक दलों में आम सहमति जरूरी है।

इस समय दो वर्ष या उससे अधिक की सजा पाने वाला व्यक्ति जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत छह साल तक चुनाव लड़ने के अयोग्य है। लेकिन अगर गंभीर अपराधों में दोषी पाए गए व्यक्ति को आजीवन चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहराया जाना है तो इसके लिए जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन करना होगा। यह काम संसद को ही करना है।

अगर आम सहमति के आधार पर सरकार कोई कानून बनाना चाहेगी तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को रास्ते से हटाने के लिए इसके प्रावधानों का दुरुपयोग नहीं हो। राजनीति को अपराधीकरण से मुक्त कराने का न्यायपालिका और निर्वाचन आयोग के स्तर पर पिछले तीन दशकों से प्रयास चल रहा है। इसमें काफी सफलता भी मिली है। न्यायिक हस्तक्षेप का ही नतीजा है कि अब दो साल या इससे ज्यादा अवधि की सजा होने पर पीठासीन सांसद और विधायक भी पद के अयोग्य हो जाता है और उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है।

भाजपा नेता और अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय लंबे समय से प्रयत्नशील है कि अदालत से दोषी ठहराये गए नेताओं के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाया जाए लेकिन उन्हें इसमें अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। उपाध्याय का दावा है कि विधायिका में करीब 30 प्रतिशत निर्वाचित प्रतिनिधियों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं। लेकिन, इनके निपटारे में अत्यधिक विलंब होने की वजह से इन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बाहर नहीं किया जा सकता है। उनकी दलील है कि आपराधिक मामले में दोषी ठहराये गए लोक सेवक और न्यायिक अधिकारियों पर आजीवन प्रतिबंध होता है लेकिन नेताओं के मामले में ऐसा नहीं है।

प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने पिछले महीने ही केन्द्र सरकार से सवाल किया था कि क्या वह अदालत से सजा पाने वाले नेताओं के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार है? शीर्ष अदालत का कहना था कि इस संबंध में केंद्र को ही निर्वाचन आयोग से परामर्श करके जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन करने का फैसला लेना होगा। हालांकि, केन्द्र सरकार अभी तक दोषी और सजायाफ्ता नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाने के पक्ष में नहीं है, लेकिन अब उसे एक बार फिर शीर्ष अदालत में अपनी स्थिति साफ करनी है ताकि जनहित याचिका पर कोई निर्णय हो सके।

राजनीति को अपराधीकरण से मुक्त कराने के प्रयासों के दौरान ही न्यायालय में एक अन्य मामला आया था, जिसमे गंभीर अपराध के आरोपों का सामना कर रहे व्यक्तियों को चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित किया जाए। शीर्ष अदालत ने अपनी व्यवस्था में कहा कि कानून में अपेक्षित प्रावधान के अभाव में वह गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे किसी भी निर्वाचित प्रतिनिधि को अयोग्य घोषित नहीं कर सकता।

संप्रग सरकार के कार्यकाल के दौरान पूरी संजीदगी के साथ यह मुद्दा उठा था कि ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने के अयोग्य बनाया जाए, जिनके खिलाफयौन शोषण, बलात्कार, बलात्कार के प्रयास, हत्या, हत्या के प्रयास, आतंकी गतिविधियां, धनशोधन और भ्रष्टाचार जैसे गंभीर अपराधों के आरोप में अदालतों में अभियोग निर्धारित हो चुके हैं, लेकिन राजनीतिक दलों में आम सहमति नहीं बनी।

अनुप भटनागर

ऐसी स्थिति में निर्वाचन आयोग ने सुझाव दिया कि, राजनीतिक दलों को गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे व्यक्तियों को चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार नहीं बनाना चाहिए और ऐसा करके आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को संसदीय व्यवस्था के दायरे से बाहर रखना संभव होगा। इसके बाद, शीर्ष अदालत ने राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों का आपराधिक मामलों सहित पूरा विवरण राजनीतिक दल की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के साथ ही स्थानीय समाचार पत्रों में इनके विज्ञापन देने का आदेश दिया था।

बहरहाल, सरकार और राजनीतिक दलों के ढुलमुल रवैये के बावजूद राजनीति को अपराधीकरण से मुक्त कराने के न्यायपालिका और निर्वाचन आयोग के प्रयास जारी हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि देर-सवेर सरकार और प्रमुख राजनीतिक दल लोकतांत्रिक प्रक्रिया को स्वच्छ बनाने के लिए एकजुट होंगे।

जलाऊ लकड़ी की चाह में जंगल का हो रहा सफाया..., वन अमले की लापरवाही हो रही उजागर

माही की गूंज, भानपुरा। साहिल अगवान

नगर भानपुरा के समीपस्थ छोटे-बड़े महादेव एवं अरावली की पहाड़ियों पर विगत कुछ वर्षों से जंगल लगातार घने होते जा रहे थे। जिससे पर्यावरण प्रेमी काफी खुश थे। यही नहीं यहां पर वर्षा काल में बड़े महादेव सहित छोटे महादेव बिजोलिया, चतुर्भुज नाथ, कथिरिया सहित अनेक स्थानों पर प्रतिदिन हजारों पर्यटक प्रकृति की गोद में अपने शहरों से कहीं दूर आकर हरियाली झरने धार्मिक क्षेत्रों का भरपूर आनंद ले रहे थे। वहीं अब लगातार विगत एक माह से जलाऊ लकड़ी की चाह में नगर की अनेक मजदूर वर्ग की महिलाएं प्रतिदिन घने व हरे-भरे पेड़-पौधों को काटने में लगी हुई है। वहीं वन विभाग भानपुरा यदा-कदा अपनी ड्यूटी निभा कर चैन की नींद सोए हुए हैं। इसी के कारण उपरोक्त क्षेत्र के जंगल तेजी से नष्ट हो रहे हैं। प्रकृति प्रेमी प्रातः काल भ्रमण करने वाले क्षेत्रवासी अपने जंगलों की बेरहमी से कटाई देखकर आक्रोशित हो खून का घूंट पीने को

मजबूर है, परंतु जवाब देह वन विभाग जागने को तैयार नहीं है। उच्चाधिकारी भी लगता है इस ओर से आंखें मूंदे हुए हैं। यदि तेजी से कटते हुए छोटे बड़े महादेव व पहाडों के पेड़ पौधों को नहीं बचाया गया तो निश्चित ही आने वाले समय में यहां पेड़ों का दिखना मुश्किल हो जाएगा। एक और शासन प्रशासन राज्य व केंद्र सरकार वनों को बचाने में बड़े बड़े वादे व योजनाएं लाते हैं परंतु ऐसा ही चलता रहा तो यहां के जंगल जल्दी ही पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है।

वन रेंजर कमलेश सालवी ने बताया कि, हमें कटाई की सूचना मिली थी इस पर वन अमले ने कार्रवाई करते हुए कुछ महिलाओं के लकड़ी सिर बोझ को जप्त किया है। महिलाएं मौके से भागने में सफल रही है,आगे भी कार्रवाई सख्त की जाएगी एवं जंगलों को हर हाल में बचाया जाएगा। वन रेंजर सालवी ने बताया कि, मुखबीर बिठाए गए हैं एवं समय-समय पर वन अमला जंगलों की निगरानी करने हेतु और मुस्तैदी से कार्य करेगा।

लापरवाह बीएमओ डॉ. चौहान निलंबित

मामला: संबल योजना के तहत हितग्राही की सहायता राशि को रोकने का

माही की गूंज, मंदसौर।

उज्जैन संभागायुक्त संदीप यादव ने संभाग के मंदसौर जिले के सीतामऊ विकास खण्ड के विकास खण्ड चिकित्सा अधिकारी डॉ.अरविंद चौहान की गंभीर लापरवाही के कारण तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है। संभागायुक्त ने म.प्र. सिविल सेवा नियम के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए निलम्बन आदेश जारी किया है। निलम्बन आदेश की प्रभावशीलता के दौरान डॉ. चौहान का मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय जिला मंदसौर रहेगा। निलम्बनकाल में डॉ.चौहान को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता रहेगी।

ये है मामला

मध्यप्रदेश में ऐसे हजारों मामले हैं परंतु यह मामला मुख्यमंत्री तक पहुंच गया था इसलिए फटाफट कार्रवाई की गई है। मिली जानकारी अनुसार सीतातऊ तहसील के ग्राम सेमली निवासी रमेशलाल मेघवाल की पत्नी जस्सूबाई की प्रसूति 13 अक्टूबर 2020 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुवासरा में हुई थी। शासन की योजनाओं के तहत जननी सुरक्षा योजना के एक हजार 400 रुपए व संबल के अंतर्गत प्रसूति सहायता योजना के 12 हजार रुपए जस्सूबाई को मिलना था। पर समय पर सहायता राशि नहीं मिली।

रमेशलाल ने अस्पताल प्रभारी चिकित्सक से लेकर बीएमओ, सीएमएचओ तक को शिकायत की पर उसे मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना अंतर्गत प्रसूति सहायता राशि नहीं मिली। तब जाकर इसी वर्ष 5 अप्रैल को समाधान ऑनलाईन में शिकायत दर्ज कराई तो भी एल वन पर सीतामऊ बीएमओ डॉ. अरविंद चौहान ने कोई कार्रवाई नहीं की। 24 अप्रैल को शिकायत एल टू सीएमएचओ डॉ. केएल राठौर के पास पहुंची तो सीएमएचओ ने जवाब दिया कि, मामले में बीएमओ द्वारा कार्रवाई की जा रही हैं। कोई कार्रवाई नहीं होने पर 30 अप्रैल को शिकायत उच्च स्तर पर चली गई।

इस मामले में एक रोचक तथ्य यह था कि, रमेशलाल प्रसूति सहायता राशि नहीं मिलने की शिकायत कर रहा था और बीएमओ डॉ. जैन जवाब लिख रहे थे कि, संबल योजना में भुगतान नहीं होने से निराकरण दर्ज किया जाए पर इससे शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं हुआ। शिकायत 20 सितंबर को जननी सुरक्षा राशि के भुगतान हेतु बजट आवंटन प्राप्त होने पर भुगतान करने जाने का उल्लेख करते हुए शिकायत फोर्सली बंद कर दी गई। मामला सीएम तक पहुंच गया तो ताबड़तोड़ 15 नवंबर को प्रसूति सहायता के एक हजार 400 रुपए महिला के खाते में डाले गए। इसके अलावा 4 दिसंबर को संबल योजना के तहत 11 हजार 600 रुपए भी खाते में डाले गए।

कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय से लापता हुए तेन्दुएं का किया रेस्क्यू

माही की गूंज, इन्दौर।

कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय से लापता हुए तेन्दुएं का सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया गया तथा तेन्दुए को स्वास्थ्य परीक्षण एवं आगामी उपचार हेतु कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय को सौंपा गया है।वनमण्डलाअधिकारी वनमंडल इंदौर द्वारा बताया गया कि, वन मण्डल बुरहानपुर से रेस्क्यू कर लाया गया तेन्दुआ एक दिसम्बर से कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय से लापता हो गया था। वन विभाग के रेस्क्यू दल, क्षेत्रीय अमले तथा चिडियाघर के स्टाफ एनजीओ स्कोल द्वारा लगातार तेन्दुए की चिडियाघर एवं आसपास के क्षेत्र में खोज की जा रही थी। 6 दिसम्बर को सुबह सूचना प्राप्त होने पर स्निफर डॉग द्वारा रेसीडेंसी एरिया, संवाद नगर क्षेत्र में रेस्क्यू दल द्वारा सर्च किया गया। पुनः रात्रि साढ़े 9 बजे रेडियो कॉलानी इन्दौर निवासी आशीष गुप्ता द्वारा तेन्दुए के देखे जाने की सूचना प्राप्त हुई। रात्रि में रेस्क्यू दल रालामण्डल एवं वन कर्मचारियों द्वारा दोबारा एरिया सर्च किया गया। 7 दिसम्बर को प्रातः साढ़े 10 बजे तेन्दुए को नवरतन बाग क्षेत्र में स्थानीय रहवासियों द्वारा देखा गया। सूचना प्राप्त होने पर रालामण्डल रेस्क्यू दल, क्षेत्रीय अमले, वेटनरी डॉक्टर श्री उत्तम यादव, एनजीओ स्कोल से श्री ब्रजेश विक्रम को मौके पर पहुंचने हेतु सूचित किया गया। वन विभाग की रेस्क्यू टीम, चिडियाघर एवं अन्य क्षेत्रीय अमले तथा एनजीओ स्कोल द्वारा मुख्य वनसंक्षक इन्दौर वृत्त एचएस मोहन्ता के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन तथा वनमण्डलाधिकारी बुरहानपुर प्रदीप मिश्रा एवं वनमण्डलाधिकारी इन्दौर नरेन्द्र पण्डवा की उपस्थिति में तेन्दुएं का सफलतापूर्वक फिजीकल रेस्क्यू किया गया तथा तेन्दुए को स्वास्थ्य परीक्षण एवं आगामी उपचार हेतु कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय को सौंपा गया।

सड़क पर पड़ी मिली संबल योजना

माही की गूंज, मंदसौर।

महू-नीमच राजमार्ग से सटे औद्योगिक क्षेत्र में मंगलवार को भावना रेस्टोरेन्ट के समीप सड़क पर संबल योजना के श्रमिक कार्ड पड़े हुए देख क्षेत्र के लोगों ने अधिकारियों को सूचना दी। इसके बाद सहायक श्रम अधिकारी प्रकाश डोडवे व अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने सड़क पर पड़े श्रमिक कार्ड को एकत्र कर थेले में भरे और यहां से ले गए। कार्ड यहां पर किसने और क्यों फेंके या किसी तरह गिर गये, इस संबंध में अब तक अधिकारियों को कुछ पता नहीं चल पाया है।

श्रम अधिकारियों का कहना है कि, मौके से मिले संबल योजना के श्रमिक कार्डों में से कुछ कार्ड को देखा गया है जो ग्राम पंचायत गुर्जरबर्डिया के पाए गए है। इस संबंध में श्रम विभाग के अधिकारियों ने जनपद मंदसौर को सूचना दी है। अब मामले में आगामी कार्रवाई जनपद द्वारा की जाएगी।

मंदसौर सहायक श्रम अधिकारी प्रकाश डोडवे ने बताया कि, ओद्योगिक क्षेत्र में भावना रेस्टोरेन्ट के समीप सड़क पर संबल योजना के श्रमिक कार्ड पड़े होने की सूचना मिली थी। इसके बाद मौके पर पहुंचे, सड़क पर करीब 150

श्रमिक कार्ड बिखरे हुए पड़े थे। सभी कार्ड एकत्रित कर जब्ती में लिए। कुछ कार्ड चेक किए है, जिनमें ग्राम पंचायत गुर्जरबर्डिया के कार्ड होना पाए गए है। इस संबंध में सीईओ जनपद पंचायत मंदसौर को लिखा है। अब मामले में जांच जनपद मंदसौर द्वारा की जाएगी।

सूदखोरों के खिलाफ पुलिस एक्शन में

माही की गूंज, मंदसौर।

कर्ज से दबे व परेशान व्यक्तियों को राहत देने के लिए पुलिस द्वारा जिले में सूदखोरी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही पुलिस द्वारा अभियान के संबंध में परचे वितरण व हेल्पडेस्क सहित सोशल मीडिया से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। एक महीने में सूदखोरी मामले में करीब 7 केस दर्ज किए हैं।

शहर कोतवाली टीआई अमित सोनी ने बताया, बिना लाइसेंस के सूदखोर अधिक ब्याज लेकर लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। अधिकतर सूदखोर जरूरत पड़ने पर कोरे चेक ले लेते हैं। बाद में मनचाही रकम भरकर इन्हें बैंक में लगाकर बाउंस करा लेते हैं। इसके बाद न्यायालय में केस फाइल कर

देते हैं। कई दबाव में आकर लोग गलत कदम उठा लेते हैं। कोतवाली पुलिस द्वारा चौराहों पर परचे व डेस्क लगाकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। मंगलवार को भी बीपीएल चौराहा पर हेल्पडेस्क लगाई। 2 से 20 प्रतिशत तक करते हैं ब्याज की वसूली आमतौर पर इस कारोबार में 2 प्रतिशत तक ब्याज ठीक माना जाता है लेकिन लाइसेंस के बिना सूदखोर 20 प्रतिशत तक ब्याज वसूलते हैं। जानकारी के अनुसार इन मामलों में अधिकांश विवाद की स्थिति बन जाती है।

इन नंबरों पर कर सकते हैं शिकायत

सूदखोरों के खिलाफसूचना देने के लिए पुलिस ने नंबर जारी किया है। संबंधित शिकायत के लिए 7049132031 या 07422- 220500 पर कॉल कर सकते हैं। पुलिस संबंधित पर जांच के बाद कार्रवाई करेगी।

एसपी सुनीलकुमार पांडेय ने बताया कि, पूरे जिले में सूदखोरी के खिलाफअभियान चलाया जा रहा है। इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। पिछले महीने में करीब 7 प्रकरण दर्ज हुए हैं। जांच के बाद संबंधितों पर कार्रवाई की जाएगी।

विस्फोटक या खतरनाक ज्वलनशील वस्तुओं के भंडारण पर लगा प्रतिबंधित

माही की गूंज, रतलाम।

जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत रतलाम शहर नगर निगम सीमा क्षेत्र के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। जिसके अनुसार नगर निगम सीमा क्षेत्र में किसी भी प्रकार के विस्फोटक या खतरनाक ज्वलनशील वस्तुओं का भंडारण आदि किया जाना प्रतिबंधित किया गया है। जिला दंडाधिकारी द्वारा उक्त आदेश एसडीएम रतलाम शहर, नगर पुलिस अधीक्षक रतलाम के संयुक्त पत्र तथा निगमायुक्त के द्वारा प्रस्तुत पत्र के आधार पर जारी किया गया है।

जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि, रतलाम नगर निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत रहवासी क्षेत्रों में नगर तथा ग्राम निवेश विकास योजना के निवेश क्षेत्र में निर्दिष्ट एवं मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानों के विपरीत वैज्ञानिक रूप से संचालित कबाड़ दुकान, गोडाउन, लकड़ी के गोडाउन, प्लास्टिक, प्लास्टिक से निर्मित सामग्री, तेल, आइडियल गैस सिलेंडर गोडाउन एवं अन्य खतरनाक ज्वलनशील वस्तुओं के भंडारण इत्यादि के संचालको, भंडारणकर्ताओं को आदेशित किया जाता है कि वह अपनी अपनी दुकान, गोडाउन भंडारगृह इत्यादि को तत्काल प्रभाव से रतलाम नगर निगम सीमा क्षेत्र के बाहर समुचित स्थान पर स्थानांतरित करें। इसके लिए समय अवधि आगामी 20 दिसंबर नियत की गई है। आदेश में कहा गया है कि, रतलाम नगर निगम सीमा क्षेत्र की परिधि में कोई भी व्यक्ति, संचालक, भंडारणकर्ता द्वारा कबाड़ दुकानों, गोडाउन, लकड़ी के गोडाउन, प्लास्टिक, प्लास्टिक से निर्मित सामग्री, डीजल, गैस सिलेंडर गोडाउन, किसी भी प्रकार के विस्फोटक एवं खतरनाक ज्वलनशील वस्तुओं का भंडारण किया जाना प्रतिबंधित रहेगा।

उल्लेखनीय है कि, सिटी एसडीएम, सीएसपी तथा निगम आयुक्त द्वारा जिला दंडाधिकारी को प्रस्तुत पत्रों के आशय अनुसार रतलाम नगर निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत अवैधानिक रूप से संचालित की जाने वाली कबाड़ दुकानों, गोडाउन, लकड़ी के गोडाउन, प्लास्टिक, प्लास्टिक से निर्मित सामग्री, तेल, ऑयल, डीजल, गैस सिलेंडर गोडाउन एवं अन्य खतरनाक ज्वलनशील वस्तुओं के भंडारण इत्यादि से क्षेत्र के रहवासियों को बाधा, क्षति या मानव जीवन के स्वास्थ्य को खतरे का या लोक प्रशांति विक्षुब्ध होने का या आगजनी व कोई अन्य अप्रिय घटना घटित होने की संभावना बनी रहती है। विगत दिनों रतलाम शहर के मोहन नगर में संचालित एग्रीकल्चर पाइप्स के अवैध गोडाउन में घटित आगजनी पर कई घंटों के प्रयास उपरांत आग पर काबू पाया जा सका था। ऐसी घटना से मानव जीवन स्वास्थ्य को खतरे के साथ-साथ कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। भविष्य में इस प्रकार की अग्नि दुर्घटना नहीं हो, इसके दृष्टिगत उपरोक्त आदेश जारी किया गया है।

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण शिविर का होगा आयोजन

माही की गूंज, शाजापुर।

अध्यक्ष विद्युत शिकायत निवारण फोरम इंदौर एवं उज्जैन ने बताया कि, विद्युत नियामक आयोग के निर्देशानुसार शाजापुर जिला अन्तर्गत जिला मुख्यालय शाजापुर पर विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम शिविर का आयोजन 10 दिसंबर को श्रम कल्याण केन्द्र विद्युत नगर लालघाटी शाजापुर पर दोपहर साढ़े 12 बजे से डेढ़ बजे तक किया जाएगा। सुनवाई का समय आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है।

अधीक्षण यंत्री ने शाजापुर जिले के विद्युत उपभोक्ताओं से अनुरोध किया है कि, वे अपने क्षेत्र के कार्यपालन यंत्री अथवा सीधे अधीक्षण यंत्री कार्यालय को 2 प्रतियों में आवेदन प्रस्तुत कर उक्त शिविर का लाभ लेकर विद्युत संबंधी समस्याओं का निराकरण करवा सकते है। भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126, 127, 135 से 140 के अंतर्गत दर्ज प्रकरणों पर उक्त फोरम द्वारा सामान्यतः सुनवाई नहीं की जायेगी। जिन उपभोक्ताओं द्वारा समयावधि पूर्व आवेदन प्रस्तुत कर पंजीयन करवाया जाएगा, उनकी शिकायत का निराकरण फोरम की बैठक-शिविर में तत्काल किया जाएगा, अन्यथा उनके आवेदनों की सुनवाई नियमानुसार इन्दौर/उज्जैन मुख्यालय पर होगी।

बेखौफ बदमाशों ने अलग-अलग थाना क्षेत्र में चोरी की घटना को दिया अंजाम

माही की गूंज, भानपुरा।

तीन अलग-अलग थाना क्षेत्र में बदमाशों ने सूने मकान को निशाना बनाया। बदमाश यहां से नकदी वे जेवर ले गए। वारदात भावगढ़, नारायणगढ़ व भैंसोदामंडी चौकी क्षेत्र में हुई है। चौकी पुलिस ने बताया, मालीपुरा निवासी इखलाक हुसैन ने शिकायत दर्ज कराई। बताया कि, सोमवार दोपहर से उनका पूरा परिवार शादी में झालावाड़ गया था। बदमाश पीछे के दरवाजे से घर में दाखिल हुए और आलमारी में रखी नकदी व जेवर ले गए। मंगलवार सुबह जब परिवार लौटा तो जानकारी हुई। इसी प्रकार गरोड़ा निवासी राजेंद्र पिता रतनलाल सोनी ने भावगढ़ थाने में शिकायत कर बताया कि, बदमाश घर में घुस कर सोने के टॉप्स व चांदी के जेवर ले गए। नारायणगढ़ थाने में साबूखेड़ी निवासी जगदीश पिता देवीलाल बागरी ने शिकायत दर्ज कराई कि, बदमाश उनकी बेटी की शादी के लिए बनवाई गई ज्वेलरी ले गए। तीनों मामलों में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की।

राजनीतिक दलों व संगठनों ने मनाया

डॉ. अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस

आप पार्टी ने मनाया महापरिनिर्वाण दिवस।

कांग्रेस ने मनाया महापरिनिर्वाण दिवस।

अखिल भारतीय बलाई महासभा ने रक्तदान कर मनाया महापरिनिर्वाण दिवस।

माही की गूंज, शाजापुर।

डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौराहा महापुरा पर आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर माल्यार्पण करते हुए शोकाकुल रूप से नमन किया स कार्यक्रम में मुख्य रूप से अनिल कदम, राजेश गुप्ता, मुकेश गुजराती, विनोद जाटव, वकील खान, राजेश सिसनोरिया व पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता उपस्थित थे।

रक्तदान कर मनाया महापरिनिर्वाण दिवस

अखिल भारतीय बलाई महासभा नई दिल्ली के राष्ट्रीय युवा संरक्षक महेंद्र सिंह सोलंकी (सांसद) एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष व संस्थापक बाबूलाल बछेर साहब (पूर्व विधायक) के निर्देशानुसार बलाई महासभा के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलीप सिंह बामनिया के नेतृत्व में जिला अस्पताल शाजापुर में प्रतिवर्ष अनुसार इस बार भी बाबा साहब भीमराव आंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर आयोजित कर बाबा साहब को रक्तदान कर श्रद्धांजलि दी गई। जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक प्रभारी, आरएमओ डॉ. मनोज पंचोली, टेक्नीशियन प्रशांत वैध, अरविंद बंसोड़, बलाई महासभा के पदाधिकारी, युवा प्रदेश प्रवक्ता अनिल मालवीय, सम्भाग महासचिव अरुण गोयल, संभाग प्रभारी विजय मकवाना, जिला अध्यक्ष नारायण सिंह मालवीय, जिला सलाहकार रामचंद्र धानुक, जिला उपाध्यक्ष अर्पित परिहार, आईटी सेल संभाग प्रभारी यस पिंकू मालवीय, आईटी, सेल जिला अध्यक्ष राजा मेवाडा, जिला सचिव धर्मेंद्र मालवीय, नरेंद्र मालवीय, माखन परिहार, राकेश मेवाड़ा, सावन मालवीय, डॉ. विजेन्द्र कटारिया, डॉ. राजेश माँगरोलिया, तहसील उपाध्यक्ष विजय मेवाड़ा, राजकुमार सौराष्ट्रीय, जितेंद्र मालवीय, सिंघी भैया, मीडिया प्रभारी राजेश सिसनोरिया आदि उपस्थित थे।

कांग्रेस ने मनाया महापरिनिर्वाण दिवस

पूर्व कानून मंत्री बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर कांग्रेस जनों ने अम्बेडकर पार्क में बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की और उपस्थित अतिथियों ने बाबा साहब के जीवन और संविधान पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव गजेंद्र सिंह सिसोदिया, बार एसोसिएशन अध्यक्ष अजय पाल सिंह जादौन, कार्यकारी जिलाध्यक्ष केदार सिंह मेवाडा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मंगल सिंह राठौर, एडवोकेट शैलेंद्र सक्सेना, कयूम खान, महिपाल सिंह बेस, जगदीश मकवाना, विधानसभा कांग्रेस प्रवक्ता अजय मोरटे, पूर्व पार्षद उदय सिंह सिसोदिया, विधानसभा कांग्रेस प्रवक्ता अजय मोर्टे, पियूष शर्मा, विशाल शर्मा, जेपी मीणा, गोलू चंदेल, राहुल बिलवान, ईस पठान, सिद्दीक पठान सहित कई कार्यकर्ता एवं आमजन मौजूद थे।

एसपी की मुहिम के बाद भी क्षेत्र में धड़ल्ले से बिक रही अवैध शराब

आबकारी की मौन स्वीकृति से डायरी से जगह-जगह बिक रही अवैध शराब

माही की गूंज, रतलाम।

शराब जिस पर लगाए गए टैक्स से सरकारों को मोटा पैसा टैक्स के रुप में मिलता है। अगर शराब पर लगे टैक्स की बात करें तो यह राज्यों की कमाई का सबसे अहम जरिया है। यह बात कोरोना काल में सबके सामने जब आई थी तब शराब की दुकाने कोरोना संक्रमण में बंद थी और वापस सरकार के आदेश के बाद खोली गई। तब जनता के सामने खबरों के जरिए जानकारी सामने आई थी कि, सरकार को सबसे अधिक टैक्स शराब से ही मिलता है। इसलिए बहुत सारें नियमों को ताक में रखकर काम किया जाता है। आबकारी विभाग के वैसे तो बहुत सारे नियम है कुछ शराब ठेकेदार पालन करते है और कोई नहीं करता है। मगर आज हम एक ऐसे नियम को जानने की कोशिश करेगें जिससे सरकार को तो राजस्व का बहुत बड़ा घाट है और अवैध शराब बेचने का सबसे बड़ा अवैध सिस्टम है। जो डायरियों के माध्यम से शराब की दुकानों के ठेकेदारों द्वारा किया जाता है जो वर्षो से निरतंर जारी है। बस बंद उस समय होता है जब पुलिस का अवैध शराब के खिलाफ कुछ बड़ा अभियान चलता है तब थोडे बहुत दिनों के बाद स्थिति सामान्य होने पर फिर से यह अवैध शराब के डायरियों खेल चालू हो जाता है।

कई वर्षों से जारी है यह खेल

ऐसा नहीं कि गांवो में डायरियां के माध्यम से अवैध शराब बेचने वालों पर कार्रवाई नहीं होती, जब भी अवैध शराब को लेकर प्रदेश स्तर व जिला स्तर पर अभियान चलता है तब क्षेत्र के ठेकेदारों और गांव में मयखाने खोलने वालों को सूचना दे दी जाती है, वह अपने किसी व्यक्ति या खुद पर कम मात्र या कुछ शराब के क्वार्टर या एक दो शराब की पेटी का केस दर्ज करवाकर छुटने के बाद फिर से यह अवैध शराब का धंधा करने लग जाते है। जबकि जमीन स्तर पर जाकर देखा जाएं तो उक्त व्यक्ति पर अवैध शराब की कार्रवाई के बाद उसका यह अवैध शराब का धंधा बंद नहीं होता उसकी जगह और कोई करता है। ऐसा अवैध नियमों का चलन वर्षो से ग्रामीण क्षेत्रों में है और यही अवैध शराब बेचने का सबसे बड़ा केन्द्र है। डायरियों के माध्यम से क्षेत्र के शराब ठेकेदार से ली गई शराब के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध शराब का धंधा करने वाले एजेंट सस्ते दामों में अवैध शराब बेचते हैं जो नियमों के विरुद्ध तो है और शराब पीनेवालों के साथ स्वास्थ्य से खिलवाड़ भी होता है।

वैसे तो यह अवैध शराब बेचने का तरीका वर्षो पुराना है लेकिन पिछले करीबन 10 वर्षो से शराब के ठेकेदारों द्वारा अपनी एक नियमों की परिपाटी बना दी गई है। जिसके अनुसार इनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में शराब बिकवाने के लिए शराब की दुकानों से डायरियां बनाकर दे रखी है, जिसका इन्होंने ने खुद का शुल्क निर्धारित भी गांव और शराब के धंधे से मीली अवैध कमाई के लिए कर रखा है। जंहा जीतने अधिक शराब प्रेमी (पीने वाले) लोगे उसके हिसाब से शुल्क कहीं पर 5 हजार तो कई पर 10 हजार रुपए लेकर डायरियों को बनाकर गांव में अवैध शराब बेची जा रही है।

सूत्रों अनुसार इन डायरियों में ठेकेदार से किस एजेंट और किसी गांव के एजेंट ने कितनी शराब ठेकेदार से खरीदी गई और बेची गई उसका लेखा-जोखा रखा जाता है। जिससे शराब ठेकेदारों के ऐरिया सेल्समैनों को यह जानकारी प्राप्त हो सकें कि, उक्त डायरियों के माध्यम से ठेकेदार की गांव में अवैध शराब बेचने वालों ने कितनी शराब बेची गई और इसी की आड़ लेकर गांव के अवैध शराब माफिया ब्लैक की सस्ते दामों में शराब खरीदकर यह अवैध धंधा करते हैं। आबकारी विभाग की मिलीभगत का अंदाज़ा इसलिए लगाया जा सकता है कि, यह डायरियों का खेले वर्षो से निरंतर जारी है।

पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी ने जब से जिले की कमान संभाली है तब से कुछ हदों तक इन अवैध शराब के माफिया में खौफहै। इसी कारण यह डायरियों का खेले गुपचुप तरीके से चल रहा है। ऐसा नहीं है कि, थाने की पुलिस को इसकी जानकारी नहीं होती है जानकारी सभी को होती है थाने क्षेत्र के बिट प्रभारियों को सब जानकारी रहती है। सूत्रों द्वारा बताया जाता है कि, मासिक नगद भेट राशि तय होती है जो गांव में डायरियों से शराब बेचने वाले एजेंटों या ठेकेदार द्वारा दी जाती है और यह नगर भेट राशि थाना प्रभारी तक पहुंचती है इसलिए छोटीमोटी कार्रवाई कर सरकारी आकड़ों की खानापूर्ति की जाती है। डायरियों से शराब बेचने का गोरखधंधा, अवैध कमाई का सबसे बड़ा धंधा है। डायरियों के माध्यम से बनाएं गए ऐजेंटों द्वारा अवैध शराब बेचने का क्रम वर्तमान में जारी है।

कालूखेड़ा थानांतर्गत जो भी ग्रामीण क्षेत्र के ठेकेदारों द्वारा डायरी देकर नियुक्त किए गए ऐजेंट को रोजाना शराब ठेकेदार का चार पहिया वाहनों द्वारा से गांव-गांव जाकर शराब सप्लाई की जाती है और यह सब खुलेआम होता है। पुर्व में नामली क्षेत्र में अवैध शराब से हुई मौतों के मामले में कठोर कार्रवाई हुई थी। तब अवैध शराब माफिया भूमिगत हो गए थे लेकिन जब से सरकार ने लॉकडाउन के बाद ठेकेदारों को शराब के ठेके नियमों के अनुसार आवंटित किए हैं तब से यहा डायरियों का चलन चल गया है। डायरियों के माध्यम से ठेकेदारों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में गुपचुप तरीके से यह अवैध शराब का धंधा जारी है। पूर्व में जिले के जावरा के सोहनगढ़ व नामली थानांतर्गत हुएं अवैध शराब कांड को देखकर अवैध शराब का सेवन करने वाले लोगों को भी यह ध्यान देना जरूरी है कि, अवैध शराब स्वास्थ्य पर सबसे बड़ा घातक साबित होती है, इससे देशभर में कितने ही लोग मौत के आगेश में चले जाते है जिसके देशभर में कई उदाहरण है। मगर मोटे-मोटे एक अनुमान के हिसाब से ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते दामों में कोई शराब पीता है तो वह है मजदूर गरीब वर्ग, जो किसी न किसी रुप से किस कारण से शराब का सेवन करता है वे ही यह अवैध शराब पीकर अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे है और अपने परिवार की परेशानियों का सबब बन रहे हैं। इस मामले में सबसे बड़ा जिम्मेदार आबकारी विभाग है। इनकी निरतंर चेकिंग प्रणाली तय नहीं है विभागीय खानापूर्ति कर ली जाती है इसलिए इस अवैध शराब डायरियों के माध्यम से बेचें जाने की परपंरा बनती जा रही है।

जिले में पिछले दिनों शराब के मामलों में हुए विवादों को अवैध शराब की बिक्री के मामले से आका जा रहा है। जिले के पुलिस कप्तान गुजरात और दिल्ली तक अवैध शराब के मामले में बड़ी कार्रवाई कर चुके है तो निश्चित है कि इस डायरियों से शराब बेचने के मामले में संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करेगे। मगर जिम्मेदारी तो आबकारी विभाग है कि, वह इस डायरियों के सिस्टम की परिपाटी को खत्म कैसे करते है। यह सवाल बना हुआ है। वही इस पूरे मामले को लेकर आबकारी अधिकारी जावरा अशोक दवे का कहना है कि, डायरी पर शराब बेचना अवैध है, इसको लेकर आए दिन कार्रवाई की जा रही है, और अगर ऐसी सूचना मिलती है तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

वरिष्ठ नागरिकों को किया सम्मानित

माही की गूंज,थांदला।

जिला सहकारी बैंक मर्यादित शाखा थांदला बैंक परिसर में अमानत बचत पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिक बैंक के खाता धारक मूलचंद जैन, मुरलीधर नागर, मुरलीधर वर्मा, अनवर खान, दिनेश गुप्ता एवं ग्रामीण क्षेत्रों के कृषक सदस्यों को शाल व श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम शाखा प्रबंधक पार्सिंग उंदपी ने अपने उद्बोधन में कहा कि, जिले के वरिष्ठ अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार शाखा में वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान किया गया, जिसमें नगर के पांच वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित किया गया सम्मानित करने का बैंक को सौभाग्य प्राप्त हुआ, बैंक समस्त खाता धारको का उत्कृष्ट आभार प्रकट करती हैं कार्यक्रम में बैंक कर्मी व खाताधारक उपस्थित थे।

पेंशनरो ने दिया ज्ञापन

माही की गूंज, थांदला। पेंशनर एसोसिएशन थांदला इकाई द्वारा मुख्यमंत्री के नाम अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को ज्ञापन सौंपा, ज्ञापन के मुख्य पांच बिंदु 32 एव 27 माह से लंबित एरियर प्रदान किया जाए। वर्तमान में पेंशनरों को 8 प्रतिशत डीए यथा स्थिति प्रदान करें, प्रतिमाह एक हजार चिकित्सा भत्ता प्रदान किया जाए, 80 वर्ष के स्थान पर 70 वर्ष आयु होने पर दो प्रतिशत अतिरिक्त वृद्धि प्रदान की जाए तथा पेंशन हेतु बोर्ड का गठन किया जाए। उक्त मांगों का वाचन एसोसिएशन के अध्यक्ष जगमोहन सिंह राठौड़ ने किया और संघ के पदाधिकारी डि के उपाध्याय गणपत दास बैरागी के के आचार्य अमृतलाल चौहान एसोसिएशन के सदस्यों की उपस्थिति में एस डि एम भाना को ज्ञापन प्रेषित किया ।

सम्पर्क एप पर नही दी जानकारी, 14 सुपर वाईजर का कटा एक दिन का वेतन

माही की गूंज, बड़वानी।

महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी आरएस गुण्डिया ने सम्पर्क एप पर भ्रमण की जानकारी न देने पर 14 सुपर वाईजर की एक दिन का वेतन काटने का आदेश दिया है। साथ ही पुनः समस्त सुपर वाईजरों को चेताया है कि, यदि शासन के निर्देशानुसार भ्रमण की जानकारी सम्पर्क एप पर दर्ज नहीं की जायेगी, तो दोषी सुपर वाईजरों की एक वेतनवृद्धि रोकी जाएगी।

इन सुपर वाईजरों का कटा है वेतन

सम्पर्क एप पर 8 दिसम्बर को अपने भ्रमण की जानकारी दर्ज न करने पर ठीकरी की सुपर वाईजर भागा ब्राहम्णे, निवाली की सुपर वाईजर राधा भावसार, पाटी की सुपर वाईजर बंसती भिडे एवं सुमन चैहान, पानसेमल की सुपर वाईजर भगवती वास्कले, ऋतु पंवार, मधुबाला चतुर्वेदी, चन्द्रकान्ता जैप, बड़वानी की सुपर वाईजर संध्या सोलंकी, राजपुर की सुपर वाईजर उष्मा सोलंकी, सेंधवा की सुपर वाईजर संध्या अलोने, वरला की सुपर वाईजर लीलावती शिन्दे, गीता डावर, अर्चना सोलंकी का एक दिन का वेतन काटा गया है।

नेशनल लोक अदालत में रखे जाएंगे 7 हजार प्रकरण- जिला न्यायाधीश श्री गर्ग

माही की गूंज,बड़वानी।

नेशनल लोक अदालत में पक्षकार अपने प्रकरणों का निराकरण सुलह एवं समझौते के आधार पर करवा सकता है। साथ ही कोर्ट प्रकरण से होने वाले मानसिक एवं आर्थिक दबाव को भी दूर कर सकता है। इसलिए समय-समय पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। जिससे पक्षकारों के मध्य सुलह एवं समझौता कर निराकरण करवाया जा सके। अतः पक्षकार नेशनल लोक अदालत में आकर सुलह एवं समझौते के आधार पर अपने प्रकरण का निराकरण कर लोक अदालत में दी जाने वाली छूटों का अधिक से अधिक लाभ उठाए।

उक्त बाते प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार गर्ग ने बुधवार को जिला न्यायालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। इस दौरान उन्होने बताया कि, 11 दिसम्बर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में 6 हजार 935 प्रकरण रखे जायेंगे। जिसमें 5 हजार 21 प्रीलिटिगेशन के प्रकरण तथा जनउपयोगी लोक सेवाओं के प्रिलिटिगेशन के 20 एवं अन्य प्रकरणो के एक हजार 894 प्रकरण रखे जायेंगे। इस हेतु 15 खण्डपीठों का गठन किया गया है। वार्ता के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अजय कुमार गर्ग एवं विशेष न्यायाधीश सुश्री नीना आशापुरे ने बताया कि, 11 दिसम्बर को आयोजित लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के अंतर्गत लंबित प्रकरणों में निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवाट भार तक के गैर घरेलू, 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट दी जावेगी।

सम्पत्ति कर एवं जलकर में भी दी जाएगी छूट

वार्ता के दौरान श्री गर्ग एवं सुश्री आशापुरे ने बताया कि, राज्य शासन द्वारा सम्पत्ति कर/अधिभार, एवं जलकर/जलकर अधिभार में भी 11 दिसम्बर को आयोजित नेशनल लोक अदालत में छूट दी जाएगी।

जनउपयोगी प्रकरणों में भी होगा निराकरण

वार्ता के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव आरके सोनी ने बताया कि, नेशनल लोक अदालत में जनउपयोगी लोक सेवाओं के तहत 20 प्रकरण रखे जायेंगे। उन्होने बताया कि, जनउपयोगी लोक सेवा के तहत बिजली, जल, सड़क, दूरभाष, पोस्ट, प्रकाश, बीमा, परिवहन, स्वच्छता से संबंधित शिकायत की जा सकती है। जनउपयोगी लोक सेवाओं के तहत कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत सादे कागज पर आवेदन के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बड़वानी में कर सकता है। उन्होने बताया कि, विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निराकरण कराने पर पक्षकार को न तो कोर्ट फीस देना होता है, और न ही वकील की फीस देना पड़ती है। आवेदन के पश्चात् विधिक सेवा प्राधिकरण संबंधित विभाग से पक्षकार की शिकायत का निराकरण करवाते है।

भारत में मानव संसाधन विकास की स्थिति पर विशेष व्याख्यान का हुआ आयोजन

माही की गूंज, बड़वानी।

अकादमिक उत्कृष्टता एवं आत्म निर्भर मध्यप्रदेश कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राचार्य डॉ. पुरुषोत्तम गौतम के संरक्षण एवं मार्गदर्शन में शासकीय कन्या महाविद्यालय बड़वानी के अर्थशास्त्र विभाग एवं स्वामी विवकानंद कॅरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वावधान में ÷भारत में मानव संसाधन विकास की स्थिति÷ पर विशेष व्याख्यान का ऑनलाईन आयोजन किया गया। विशेष व्याख्यान की मुख्य वक्ता डॉ. आशा साखी गुप्ता, प्राध्यापक शभीना शासकीय स्नाताकोत्तर महाविद्यालय बड़वानी हैं। व्याख्यान के पूर्व डॉ. कविता भदौरिया, अर्थशास्त्र विभाग द्वारा डॉ. आशा साखी गुप्ता का परिचय दिया गया तथा स्वागत किया गया।

डॉ. आशा साखी गुप्ता ने ऑनलाईन व्याख्यान देते हुए कहा कि, भारत में मानव संसाधन विकास का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। भारत में जनसंख्या की अधिकता है तथा मानव संसाधन विकास की स्थिति को देखने के लिए जनसंख्या की गुणवत्ता उसकी शिक्षा उसका स्वास्थ्य तथा जागरूकता की स्थिति को देखना बहुत आवश्यक है। उन्होंने बताया कि, आर्थिक विकास मुख्य रूप से मानव संसाधन विकास पर निर्भर करता है। मानवीय पूँजी श्रम शक्ति व उत्पादन का महत्वपूर्ण साधन है। उसका विकास कर के ही आर्थिक विकास किया जा सकता है।

अतः मानवीय पूँजी के विकास के लिए शिक्षा के साथ-साथ उसकी कुशलता का विकास किया जाना भी आवश्यक है। आर्थिक विकास को मापने का महत्वपूर्ण यंत्र है कि, क्या राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही? क्या आर्थिक कल्याण में वृद्धि हो रही है? इन सबका माप ही मानव विकास सूचकांक है। जिसे बनाने का श्रेय मेहबूब-उल-हक को है। जिसमें उन्होंने 3 आधार लिए है संभावित आयु, शैक्षिक प्राप्तियाँ और जीवन स्तर है।

इन तीनो आधार पर मानव विकास सूचकांक बनाया गया। इस आधार पर विभिन्न देशों की मानव विकास की स्थिति को देखा जाता है। इस संदर्भ में भारत की बात करें तो भारत की स्थिति 189 देशों में 131 पर है जो मध्यम स्थिति को दर्शाती है। अतः भारत में मानव विकास की स्थिति में सुधार की आवश्यकता है। हमारा देश और सरकारें इस स्थिति में सुधार हेतु मानव विकास के आधार पर विभिन्न रणनीतियाँ बनाकर कार्य कर रही है। मध्यप्रदेश वह पहला राज्य है जब 1995 में मानव विकास सूचकांक जारी किया गया। आज हम देखे तो मध्यप्रदेश द्वारा शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार हेतु नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य है। जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि, शिक्षा के साथ-साथ विद्यार्थियों का कौशल विकास भी किया जाए जिससे वे आर्थिक रूप से संपन्न हो सकें। अतः नई शिक्षा नीति में विभिन्न रोजगारोन्मुखी विषय जैसेः जैविक खेती, बिक्री कौशल, बागवानी, औषधीय पौधे, डेयरी प्रबंधन, पर्यटन, वर्मी कम्पोस्ट, खद्य प्रसंस्करण जैसे विषयों का समावेश किया गया है जो हमारे विद्यार्थियों का कौशल उन्नयन करते हुए भारतीय ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को मजबूती प्रदान करेंगे और देश के आर्थिक विकास में सहायक होंगे।

स्टेडिंग कमेटी की बैठक में कलेक्टर ने दी त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया की जानकारी

माही की गूंज, बड़वानी।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शिवराजसिंह वर्मा ने बुधवार को आयोजित स्टेडिंग कमेटी की बैठक में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलो के पदाधिकारियों को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 के तहत सम्पादित होने वाले निर्वाचन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी।

बैठक में कलेक्टर श्री वर्मा ने पंचायत निर्वाचन के लिए निर्धारित आदर्श आचरण संहिता, मतदान केन्द्रों की संख्या, मतदाताओं की संख्या की जानकारी दी। बैठक में बताया गया कि पंच एवं सरपंच पद का निर्वाचन मतपत्र से तथा जनपद एवं जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन के लिए मतदाता अपने मतो का प्रयोग ईव्हीएम से करेंगे।

बैठक में बताया गया कि, नाम निर्देशन प्राप्ति के साथ अभ्यर्थी को निक्षेप राशि जमा करनी होगी, जिसमें जिला पंचायत सदस्य को 8 हजार, जनपद पंचायत सदस्य को 4 हजार, ग्राम पंचायत सदस्य को 2 हजार, पंच को 400 जमा करने होंगे। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला अभ्यर्थी के मामले में उपरोक्त निक्षेप राशि का आधा भाग जमा करना होगा। नाम निर्देशन पत्र के साथ अभ्यर्थी द्वारा पंच पद के लिए निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र एवं अन्य पदों के लिए निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। नाम निर्देशन प्रस्तुति के समय अभ्यार्थी के साथ अधिकतम दो व्यक्ति प्रवेश कर सकेंगे। नामांकन प्रयोजन के लिए वाहनों की संख्या 2 तक सीमित की गई है।

बैठक में बताया गया कि, बड़वानी जिले की जनपद पंचायतों में तीन चरणों में निर्वाचन प्रक्रिया संपादित होगी। पहले चरण में राजपुर एवं ठीकरी में, द्वितीय चरण में बड़वानी, निवाली, पानसेमल तथा तृतीय चरण में पाटी एवं सेंधवा विकासखण्ड में चुनाव सम्पन्न कराया जायेगा। प्रथम चरण में 4 जिला पंचायत सदस्य, 39 जनपद पंचायत सदस्य, 122 सरपंच, 2 हजार 83 पंच पदो पर निर्वाचन करवाया जायेगा । द्वितीय चरण में 4 जिला पंचायत सदस्य, 45 जनपद पंचायत सदस्य, 128 सरपंच, 2 हजार 316 पंच पदो पर निर्वाचन करवाया जाएगा। तृतीय चरण में 6 जिला पंचायत सदस्य, 45 जनपद पंचायत सदस्य, 159 सरपंच, 2 हजार 685 पंच पदो पर निर्वाचन करवाया जाएगा।

उक्त बैठक में राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलो के पदाधिकारियों के अलावा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शिवराजसिंह वर्मा, पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला, जिला पंचायत सीओ ऋतुराजसिंह, अपर कलेक्टर श्रीमती रेखा राठौर, डॉ. शालिनी श्रीवास्तव सहित निर्वाचन के मददेनजर नियुक्त किए गए समस्त रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी, नोडल अधिकारी, मास्टर ट्रैनर उपस्थित थे।

रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को दिया प्रशिक्षण

माही की गूंज, बड़वानी। त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के दौरान नाम निर्देशन फार्म लेने हेतु नियुक्त रिटर्निंग अधिकारियों एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी तथा सब सेंटर के सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को कलेक्टरेट सभागृह बड़वानी में बुधवार को कलेक्टर शिवराजसिंह वर्मा, जिला पंचायत सीईओ ऋतुराजसिंह, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास निलेशसिंह रघुवंशी ने प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षको ने नाम निर्देशन फार्म एवं उसके साथ लिये जाने वाले शपथ पत्र, शपथ पत्र सार, घोषणा पत्र, घोषणा पत्र सार, पंचायत एवं विद्युत देयको का नो-ड्यूज प्रमाण पत्र, जमानत राशि, नाम निर्देशन पत्रों की जांच, नाम वापसी एवं प्रतीक चिन्हों का आवंटन के बारे में विस्तार से बताया ।

ज्ञातव्य है कि, जिला पंचायत सदस्य का नाम निर्देशन फार्म कलेक्टरेट कार्यालय में तथा जनपद पंचायत सदस्य का नाम निर्देशन फार्म संबंधित जनपद पंचायत मुख्यालय पर व सरपंच-पंच का नाम निर्देशन फार्म जनपदो में निर्धारित सब सेंटरों पर सहायक रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा निर्धारित तिथियों में घोषित अधिसूचना अनुसार लिया जाएगा।

प्रशिक्षण के दौरान रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को अधिसूचना के प्रकाशन के साथ नाम निर्देशन फार्म की प्रक्रिया, नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा, अभ्यर्थियों के नाम वापसी की प्रक्रिया, शपथ पत्र का प्रारूप, अभ्यर्थियों को प्रतीक चिन्ह का आवंटन की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया गया।

मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं झोलाछाप डॉक्टर, आंख बंद कर बैठा स्वास्थ्य विभाग

स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से फल-फूल रहे झोलाछाप डॉक्टर, लंबे समय से जिले में नहीं हुई कार्रवाई

माही की गूंज, अलीराजपुर।

जिले में लंबे समय से झोलाछाप डॉक्टरों की सक्रियता बढ़ती जा रही है। जिले में इन डॉक्टरों में अपनी तादात इस कदर बढ़ गई है कि, सरकारी हॉस्पिटल से ज्यादा झोलाछाप डॉक्टरों के पास मरीज पहुंच रहे हैं। ऐसे में मरीजों की जान से खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है और और स्वास्थ्य विभाग के अफसर चुप्पी साधे बैठे हुए हैं।

आदिवासी बहुल जिले में स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की उदासीनता के चलते बड़ी संख्या में फर्जी डिग्री धारी बंगाली चिकित्सक अपना क्लिनिक खोल कर ग्रामीणों का उपचार कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के संरक्षण में चल रहे बंगाली चिकित्सकों के ठिकानों पर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन द्वारा अभी तक सिर्फदिखावे की कार्रवाई ही की जा रही हैं।

आलम यह है कि, जिला मुख्यालय पर ही करीब 10-12 बंगाली चिकित्सक अपना क्लिनिक खोलकर ग्रामीणों का उपचार खुलेआम कर रहे हैं। नगर के सोरवा नाका, कुम्हार वाड़ा, वीटी रोड़, चांदपुर रोड पर बंगाली चिकित्सकों के क्लीनिक खुले हुए हैं किंतु इनके खिलाफकई दिनों से न तो स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की और न ही प्रशासन ने आकस्मिक जांच की। प्रशासन की इस अनदेखी और लापरवाही का फायदा उठाते हुए बंगाली चिकित्सक बेखौफ होकर अपना क्लिनिक चला रहे हैं। जब जिला मुख्यालय पर ही बंगाली चिकित्सकों के क्लिनिक खुले हुए हैं तो इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता हैं कि, ग्रामीण अंचल में बड़ी संख्या में बंगाली चिकित्सक कार्यरत होंगे। जिला मुख्यालय जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग का पूरा अमला होने के बावजूद इनके क्लिनिक खुलेआम चल रहे।

बीच बाजार में किया कोविड-19 टीकाकरण

माही की गूंज, अलीराजपुर।

कलेक्टर मनोज पुष्प के दिशा निर्देशानुसार में जिले में रोको-टोको अभियान संचालित किया जा रहा है। आमजन को टीके की दोनों डोज लगवाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। एसडीएम चंद्रशेखर आजाद नगर सुश्री किरण आंजना एवं बीएमओ श्रीमती चैहान के मार्गदर्शन में राजस्व पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग अमला आमजन को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। इसी दौरान टीके की दूसरी डोज नहीं लगवाने वालों को प्रोत्साहित करते हुए टीके के महत्व की जानकारी दीए जिसके बाद कई लोगों ने बाजार में टीकाकरण कराया। इस अवसर पर कोविड-19 से बचाव हेतु टीकाकरण के महत्व की जानकारी देकर सभी को कोरोना से बचाव हेतु उपाय अपनाने के लिए जागरूक किया गया।

श्री माहेश्वरी के भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष बनाने पर हर्ष

माही की गूंज, आम्बुआ।

भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता तथा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष रहे विकास माहेश्वरी जिन्होंने हाल ही में संपन्न जोबट विधानसभा उपचुनाव में विशेष भूमिका निर्वहन कर पार्टी प्रत्याशी को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। विकास माहेश्वरी को उनके कार्य का उचित उपहार स्वरूप भारतीय युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार द्वारा भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा का विशेष अनुशंसा तथा प्रदेश के समस्त जिला अध्यक्षों की सहमति से अलीराजपुर जिले के भाजपा युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया जाने पर संपूर्ण जिले के साथ-साथ आम्बुआ में जश्न का माहौल है।

कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर मिठाई खिलाकर हर्ष व्यक्त किया। विकास माहेश्वरी को भाजपा के जिला अध्यक्ष वकीलसिंह ठकराल, जोबट विधायक श्रीमती सुलोचना रावत, पूर्व विधायक माधौसिंह डावर, नागर सिंह चौहान, पूर्व जिला अध्यक्ष किशोर शाह, हीरालाल शर्मा, राकेश अग्रवाल, मंडल अध्यक्ष जुवान सिंह रावत, भरत महेश्वरी, अनिल खंडेलवाल, यश राठौड़, हुजैफ बोहरा, देवेंद्र गहलोद, नवाब खां, शुभम क्षीरसागर आदि अनेक कार्यकर्ताओं ने बधाई देते हुए वरिष्ठ नेतृत्व का आभार माना है।

ग्राम सभाओं की बैठकें रहेगी स्थगित

माही की गूंज, अलीराजपुर। कलेक्टर एवं जिला निवार्चन मनोज पुष्प ने म.प्र. पंचायत आम निवार्चन 2021-22 के मद्देनजर लागू आदर्श आचरण संहिता के तहत पंचायत आम निवार्चन 2021-22 की कार्यवाही पूर्ण होने तक ग्राम सभाओं की बैठकें कार्रवाई रखी जाने संबंधित निर्देश जारी किए है।

अपर कलेक्टर ने चैक पोस्ट का किया निरीक्षण

माही की गूंज, अलीराजपुर।

कलेक्टर मनोज पुष्प के दिशा निर्देश पर जिले के प्रवेश सीमा क्षेत्रों पर स्थित चैक पोस्टों पर कोरोना जांच एवं कोविड-19 से बचाव हेतु विशेष सावधानियों हेतु जांच एवं जागरूकता हेतु रोको-टोको अभियान प्रभावी ढंग से संचालित किया जा रहा है। जिसके तहत चांदपुर चैक पोस्ट पर अपर कलेक्टर सीएल चनाप ने पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। उन्होंने चैक पोस्ट पर तैनात मैदानी अमले को निर्देश दिए कि, प्रत्येक वाहन चालक, परिचालक से टीके की दोनों डोज लगाने कोविड अनुकुल व्यवहार अनिवार्य रूप से पालन करने के साथ-साथ यात्रियों को भी उक्त के संबंध में जागरूक करने के विशेष प्रयास किए जाए। उन्होंने यात्री बसों के अतिरिक्त अन्य वाहनों से आने-जाने वालों की स्क्रीनिंग एवं जानकारी एकत्र करने के निर्देश दिए। इस दौरान चांदपुर चैक पोस्ट पर दो वाहनों के चालक-परिचालक पर मास्क नहीं पहनने पर चालानी कार्रवाई की गई। इस अवसर पर बीएमओ कड्डीवाडा डॉ. जयदीप जमीदार सहित अन्य स्टॉफसदस्य उपस्थित थे।

जिले की सीमा पर आने-जाने वालों की हो रही स्क्रीनिंग

गुजरात राज्य की सीमा से जिले में प्रवेश स्थानों पर चैक पोस्टों पर विशेष कोविड-19 स्क्रीनिंग कैम्प स्थापित किए गए है। इस कैम्पों में राजस्व पुलिस और स्वास्थ्य विभाग का अमला प्रत्येक आने-जाने वाले की जानकारी लेकर स्वास्थ्य संबंधित जानकारी और टीकाकरण की जानकारी ले रहा है। साथ ही सभी को कोरोना से बचाव हेतु आवयक सावधानियों को अपनाने तथा टीकाकरण के दोनों डोज लेने के लिए प्रेरित कर रहे है। यहां प्रत्येक आने-जाने वाले की स्क्रीनिंग एवं स्वास्थ्य संबंधित जानकारी ली जा रही है।

विश्व दिव्यांग दिवस पर आयोजित प्रतियोगिता में दो छात्राएं रही प्रथम

माही की गूंज, आम्बुआ।

विश्व दिव्यांग दिवस पर जिला मुख्यालय पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में आम्बुआ हाई सेकेंडरी स्कूल की दिव्यांग दो छात्राओं ने प्रथम स्थान प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की।

गूंज प्रतिनिधि को संस्था प्राचार्य नरेंद्र भारद्वाज ने बताया कि, विश्व दिव्यांग दिवस पर अलीराजपुर मुख्यालय पर दिव्यांगों की खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें आम्बुआ हाई सेकेंडरी स्कूल की छात्राओं ने भी भाग लिया। आम्बुआ की दो छात्राएं क्रमशः कु. संगीता पिता मोहनसिंह कक्षा 11वीं तथा कु. अबला पीता नाहलिया कक्षा 12वी ने 100 मीटर दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया। शाला की ओर से प्राचार्य तथा स्टाफ ने उन्हें शुभकामनाएं दी।

जिले के सबसे बड़े विकास खण्ड में पहले चरण में होंगे चुनाव

त्रिस्तरीय पंचायत चुनावः पंच-सरपंच मतपत्र मतो जिपं-जनपद सदस्य ईवीएम से चुने जाएंगे

माही की गूंज, पेटलावद।

चुनाव की तारीखों का ऐलान के साथ ही स्थानीय स्तर के चुनावों को सरगर्मी तेज़ हो गई है, पूरे प्रदेश में तीन चरणों मे चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, झाबुआ जिले के अलग-अलग विकास खण्ड में तीनों चरणों मे चुनाव होना है। जिले के सबसे बड़े विकास खण्ड पेटलावद में पहले चरण में चुनाव सम्पन्न होंगे, जिले की राजनीति में पेटलावद विकास खण्ड का खासा वर्चस्व है, ऐसे में यहां के परिणाम अन्य विकास खण्ड के परिणाम को भी प्रभावित करेगे ये तय है, चुनाव को देखते हुए, पंच से लेकर जिला पंचायत के दावेदारों ने मोर्चा संभाल लिया है, आकड़ो में जानने की कोशिश करते हैं की किस प्रकार से पहले चरण में मतदाता कितने पदों पर प्रत्याशियों का भविष्य तय करेंगे।

विकास खण्ड में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या 77

77 सरपंच के लिए होंगे चुनाव, 25 जनपद पंचायत सदस्य के लिए चुनाव होंगे, 3 जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनाव, 1298 पंचों के लिए होगा चुनाव, कुल मतदाता की संख्याः 1 लाख 64 हजार 190, पुरूष मतदाता की संख्याः 80 हजार 96, महिला मतदाता की संख्याः 83 हजार 487, अन्य मतदाताः 9, कुल मतदान केंद्रो की संख्याः 292।

राज्य निर्वाचन आयोजन द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत चुनावों की तारीखों का ऐलान गत दिनों कर दिया गया है। यह प्रक्रिया 13 दिसंबर से शुरू होकर 23 फरवरी 2022 तक चलेगी। जिले के पेटलावद विकासखण्ड कि बात की जाए तो यह विकासखण्ड जिले का सबसे बड़ा विकासखण्ड है, यहां कुल 77 ग्राम पंचायतों के लिए नए सरपंच व पंच का चुनाव होना है। जिले में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। यह चुनाव मार्च 2020 में होने थे, लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण के कारणों से चुनाव टलते जा रहे थे।

नए कामों पर लगी रोक

आचार संहिता लागू होते ही अब पंचायतों में नए कामों पर रोक लग गई है। हालांकि आचार सहिंता लगने के पूर्व से चल रहे निर्माण कार्यो पर किसी तरह का असर नहीं पड़ेगा। वहीं आचार संहिता में नए काम स्वीकृत नही होंगे। न ही किसी तरह के राजनैतिक कार्यक्रम, शिलान्यास, लोकार्पण आदि कार्य हो सकेंगे। इन सभी कार्यो पर फिलहाल 16 फरवरी तक रोक लग गई है।

प्रशासन ने शुरू की तैयारियां-

पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन ने अपने स्तर पर तैयारिया शुरू कर दी है। मतदाता सूची के प्रशासन के अलावा शासन के द्वारा जो पुराने परिसीमन के आधार पर चुनाव होने है उस प्रक्रिया को लेकर भी प्रशासन के द्वारा तैयारियां कर ली गई है। जारी कार्यक्रम के अनुसार पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के दौरान ही पेटलावद विकासखण्ड में ग्राम पंचायतों के चुनाव संपन्न हो जाएंगे। आगामी 13 दिसंबर से 20 दिसंबर तक फार्म भरे जाएंगे। फार्म की समीक्षा 23 दिसंबर को होगी। 23 को ही नाम वापसी और उसके बाद ही चुनाव चिह्न का आवंटन हो जाएगा। इसके बाद 6 जनवरी 2022 को सरपंच पदो के लिए मतदान होंगे।

पूरे पेटलावद विकासखण्ड में कुल 292 मतदान केंद्रों पर मतदान संपन्न होगा। पेटलावद विकासखण्ड में शातिपूर्ण मतदान और चुनाव संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन से पेटलावद एसडीएम और जपं सीईओ को सहायक रिटर्निंग अधिकारी की जवाबदारी सौंपी गई है। इनके साथ ही तहसीलदार पंच और सरपंच के रिटर्निंग अधिकारी के रूप में कार्य देखेंगे। पूरे विकासखण्ड में कुल 11 अलग-अलग सहायक रिटर्निंग अधिकारी बनाए गए है, जो अपने-अपने क्षैत्र में उम्मीदवारों के आवेदन लेने के बाद तहसीलदार को आवेदन प्रस्तुत करेंगे। जनपद के नामांकन एसडीएम कार्यालय में जमा होंगे वहीं ऑनलाइन नामांकन दाखिल करने पर नियत समयावधि पर एक कॉपी प्रस्तुत करनी होगी।

यातायात व्यवस्था सुधारने हेतु प्लान तैयार करने के दिए निर्देश

माही की गूंज, अलीराजपुर।

कलेक्टर मनोज पुष्प की अध्यक्षता में जिला सडक सुरक्षा समिति अलीराजपुर की बैठक कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह विशेष रूप से उपस्थित थे। बैठक में कलेक्टर श्री पुष्प ने निर्देश दिए कि, जिले के ऐसे मार्ग व स्थानों का चिहांकन किया जाए जहां वाहन दुघर्टनाएं अधिक होती है। उन्होंने निर्देश दिए छोटे-बडे वाहनों की दुघर्टना, स्थल, रोड एवं दुघर्टनाएं अधिक होने के समय तथा संबंधित क्षेत्र में दुघर्टना से घायल अथवा मृत्यु संबंधित प्रकरणों की एनालिसीस रिपोट एक सप्ताह में प्रस्तुत करें ताकि संबंधित क्षेत्र में विोष प्रयास किए जाकर दुघर्टनाओं को रोका जा सके। अलीराजपुर नगर में अलग-अलग स्थानों से आने वाले तीन एवं चार पहिया वाहनों की पार्किंग व्यवस्था हेतु स्टेंट निधार्रित किए जाने हेतु स्थल का चिन्हांकन करने के निर्देश दिए तथा आमजन को आवाजाही में परेशानी ना उठाना पडे ऐसे स्थलों का चिन्हांकन किया जाए। अलीराजपुर नगर में यातायात के प्रबंध हेतु संयुक्त टीम बनाकर भ्रमण करते हुए वाहनों की पार्किंग, छोटे दुकानदारों के बैठने, सब्जी विक्रय करने वाले ग्रामीणों की बैठक व्यवस्था साथ ही टाकीज चैराहे पर आने वाले मजदूरों की बैठक, हाट बाजार के दिन मुर्गी-बकरी बाजार हेतु उपयुक्त बैठक व्यवस्थाएं हेतु उचित और सुविधाजन स्थल का चिन्हांकन किया जाकर रिपोर्ट एक सप्ताह में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री पुष्प ने निर्देश दिए कि, अलीराजपुर नगर की यातायात व्यवस्था बेहतर किये जाने हेतु प्लान तैयार कर प्रस्तुत करें। ट्रेक्टर, ट्रकों एवं अन्य बडे वाहनों पर रेडियम एवं रिफ्लेक्टर लगाए जाने की कार्रवाई सुनिचित करते हुए चालकों को यातायात नियमों संबंधित आवश्यक समझाइश दी जाए। ओव्हर लोड वाहनों पर कार्रवाई की जाए। ग्रामीण परिवहन व्यवस्था में वृद्धि के साथ-साथ उक्त व्यवस्था को बेहतर बनाए जाने हेतु विशेष प्रयास किए जाकर अधिक से अधिक परमीट प्रदान करते हुए वाहन संचालकों को ग्रामीण परिवहन व्यवस्था को बेहतर करने के प्रयासों में सहभागी बनने हेतु आवश्यक समझाइश प्रदान करने के निर्देश दिए। जिले में सडक किनारे पेडों एवं दुघर्टना क्षेत्रों में सूचना बोर्ड और ट्री रेडियम लगाए जाने के निर्देष दिए ताकि दुघर्टनाओं को रोका जा सके। बैठक में जिला परिवहन अधिकारी वीरेन्द्रसिंह यादव, यातायात प्रभारी सुभाष सतपाडिया, सीएमओ अलीराजपुर अमरदास सेनानी, एमपीआरडीसी प्रबंधक पादीदार, सीएमएचओ डॉ. प्रकाश ढोके, सिविल सजर्न डॉ. केसी गुप्ता सहित अन्य विभागीय अधिकारीगण उपस्थित थे।

प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया धारा 144 के तहत

माही की गूंज, अलीराजपुर।

कलेक्टर एवं जिला निवार्चन अधिकारी मनोज पुष्प ने मध्यप्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत आम निवार्चन 2021-22 के चुनाव एवं आगामी दिनों में त्योहारों के मद्देनजर जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। उक्त आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, हाइक, ट्विटर, एसएमएस, इंस्टाग्राम इत्यादि का दुरुपयोग कर धार्मिक, सामाजिक, जातिगत भावनाओं एवं विद्वेष को भड़काने के लिए किसी भी प्रकार के संदेशों का प्रसारण नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति उपरोक्त वर्णित सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म में किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक एवं उन्माद फैलाने वाले संदेशए फोटो, अडियो-वीडियो इत्यादि सम्मिलित है, जिसमें धार्मिक, सामाजिक, जातिगत आदि भावनाएं भड़क सकती है या सांप्रदायिक विद्वेष पैदा हो, प्रसारित नही करेगा या भेजेगा। सोशल मीडिया के किसी भी पोस्ट जिसमें धार्मिक, सांप्रदायिक तथा जातिगत भावनाएं भड़क सकती होए को कमेंट लाइक शेयर या फारवर्ड नहीं करेगा। ग्रुप एडमिन की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि, वह ग्रुप में इस प्रकार के संदेशों को रोके। कोई भी व्यक्ति सामुदायिक, धार्मिक, जातिगत विद्वेष फैलाने या लोगों तक अथवा समुदाय के मध्य घृणा वैमनस्यता पैदा करने के या दुष्प्रेरित करने या उकसाने या हिंसा फैलाने का प्रयास उपरोक्त माध्यमों से नहीं करेगा और न हीं इसके लिए प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति अफवाह या तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर भड़काने उन्माद उत्पन्न करने वाले संदेश जिससे लोगों या समुदाय विशेष में हिंसा या गैरकानूनी गतिविधियॉ उत्पन्न हो जाए, को प्रसारित नहीं करेगा और न ही लाइक शेयर या फारवर्ड करेगा तथा न हीं ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति समुदाय ऐसे संदेशों को प्रसारित नहीं करेगा जिनसे किसी व्यक्ति, संगठन, समुदाय आदि को एक स्थान पर एक राय होकर जमा होने, कौन से या कोई विशेष कार्य, गैर कानूनी गतिविधियों को करने हेतु आह्वान किया गया हो जिससे कानून एवं शांति व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना विद्यमान हो। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर अन्य आदेश तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने की दशा मे संबंधित के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं साइबर विधि तथा अन्य अधिनियम के अंतगर्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

शिव के राज में अलकेश बाकल्या का बोलबाला, गोवा में बैठकर भी पुलिस को नचा रहा अपनी उंगलियों पर

ग्रामीणों ने पकड़ी शराब, आबकारी ने मजबूरी में 3 घंटे बाद पहुंच कर बनाया प्रकरण

शराब किसकी, और कौन कर रहा था सप्लाई की पूरी जानकारी होने के बाद भी आबकारी ने बता दिया आरोपियों को फरार

माही की गूंज, टीम झाबुआ/पेटलावद।

माही की गूंज ने 25 नवंबर के अंक में ''पुलिस शिवराज सरकार की नहीं वरन माफियाओं के इशारों पर कर रही है काम'' के शीर्षक के साथ समाचार प्रकाशित किया था। जिसमें क्षेत्र में बिक रही माफियाओं की अवैध विदेशी शराब को पुलिस कार्रवाई नहीं करते हुए शराब माफिया उर्फ सरगना अलकेश बाकलिया एवं गुर्गे के इशारों पर रायपुरिया में एक पुलिसकर्मी अंडे की दुकान पर शराब ठेकेदार का हवाला देकर किस तरह से दबाव पूर्ण कार्रवाई करने जाता है और किस तरह से दुकान मालिक पुलिसकर्मी पर बरसते हैं। वही नीलेश नाम के व्यक्ति के यहां पर पुलिस जाती है और वहां अवैध विदेशी शराब बेची जाकर घर में पर्याप्त मात्रा में अवैध शराब मिलने के बावजूद पुलिस कहती है, आपने प्रकरण दे दिया था कह कर उस विदेशी शराब को जप्त नहीं करती है का समाचार पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर प्रकाशित किया था। हमने समाचार में ''शिवराज जी आप कहते हैं माफिया राज को खत्म कर देंगे पर आपके ही राज में चल रहा माफियाई राज'' के शीर्षक के साथ उक्त मामले को उजागर किया था की, शिवराज के राज में महज जनता को गुमराह करने के लिए माफियाई राज खत्म करने की बात कर रहे हैं पर यहां शिवराज सरकार की नहीं वरन माफियाओं के इशारों पर पुलिस कठपुतली बन नाच रही है और पुलिस सरकार के नहीं वरन माफियाओं के इशारों पर कार्य कर रही है।

इसका जीता जागता सार्वजनिक रूप से पुलिस भी अपनी कार्यप्रणाली के साथ अपना स्पष्टीकरण दे रही है। जिसका एक और मामला जिले के रायपुरिया थाना क्षेत्र में 3 दिसंबर को देखने मिला। हमेशा की तरह शराब माफिया अलकेश बाकलिया के गुर्गे रायपुरिया की शराब दुकान से एक चार पहिया वाहन क्रमांक एमपी 45 सी 9093 को माफिया के गुर्गे रायपुरिया मैनेजर विनोद नायक ने देशी व विदेशी शराब की पेटिया लोड करवाकर क्षेत्र में गांव-गांव में अवैध रूप से सप्लाई करने हेतु भेजी। गुर्गे अंधगति से गाड़ी हमेशा की तरह चलाकर ले जा रहे थे कि, ग्रामीणों ने उक्त वाहन को रोका और अंध गति से वाहन नहीं चलाने की समझाईश देने पर अलकेश बाकलिया के गुर्गे ग्रामीणों से हुजत करने लगे तो ग्रामीणों ने गाड़ी के अंदर झाकर देखा तो अवैध शराब की पेटीयां भरी मिली।

''माही की गूंज की नजर नहीं रहती तो पुलिस नहीं बनाती प्रकरण''

वाहन में शराब मिलने पर प्रथम फोन ग्रामीणों ने 100 डायल को किया जहां से संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं मिलने पर माही की गूंज के प्रतिनिधि को उक्त सूचना दी गई। जिसके बाद गूंज प्रतिनिधि ने भी एसडीओपी से लेकर एसपी तक व आबकारी को मामले की सूचना देनी चाहि, लेकिन एसपी साहब का फोन ही अटेंड नहीं हुआ तो एसडीओपी मैडम ने भी काफी समय बाद फोन अटेंट किया। वही आबकारी अधिकारी मामले में गुमराह करते नजर आए, तो वही ग्रामीणों ने पुलिस थाना से लेकर सभी को फोन लगाए। मामला ग्रामीणों ने सुबह 7 बजे गाड़ी रोकने का सामने आया। ग्रामीणों द्वारा रायपुरिया थाने में भी सर्वप्रथम सूचना देने के बाद भी 2 घंटे बाद गूंज प्रतिनिधि ने फोन लगाया तो थाना प्रभारी ने अपने आप को सूचना से वंचित बताया।

पूरे मामले में ऊपर तक अधिकारियों को माही की गूंज प्रतिनिधि ने फोन लगाया जब जाकर करीब 3 घंटे बाद पेटलावद वृत के अधिकारी मौके पर पहुंचे। इन 3 से साढ़े तीन घंटों में ठेकेदार एवं गुर्गो के फोन पुलिस व आबकारी के पास कार्रवाई करने हेतु मौके पर नहीं जाने के अपने निर्देश देते रहे और पुलिस शराब माफियाओं के इशारों पर नाचती रही। शराब माफिया एवं गुर्गो को पूरा मामले को रफा-दफा करने के लिए पूरा मौका भी दिया और मौके पर रायपुरिया दुकान के मैनेजर शराब माफिया का गुर्गा विनोद नायक रम्भापुरी अपने कुछ साथियों के साथ ग्रामीणों को लुभाने के लिए पहुंचा। चूंकि पूरे मामले में ग्रामीण भी तटस्थ रहे और माही की गूंज की नजरे बनी होने के कारण माफियाओं के गुर्गे मामले को रफा-दफा करने में सफल नहीं हो पाए। ठेकेदारों की रखैल बनी आबकारी के अधिकारी 3 घंटे बाद पहुंचकर कार्रवाई के लिए शराब भरें वाहन को कार्रवाई के नाम पर पेटलावद ला रहे थे लेकिन गूंज के प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में ग्रामीणों ने मौके पर ही शराब की पेटियों को खाली करवाकर मौका पंचनामा बनाने का दबाव बनाने के बाद, आबकारी ने शराब की पेटी वाहन से नीचे उतारकर सभी ब्रांड की अलग-अलग पेटियों की गिनती कर मजबूरी में मौके पर पंचनामा बनाना पड़ा। वही ठेकेदारों की रखैल कहे जाने वाली आबकारी पुलिस ने उक्त प्रकरण के साथ भी शराब माफिया को संरक्षण देते हुए किसी भी नामजद व्यक्ति के नाम से प्रकरण दर्ज नहीं कर अज्ञात आरोपियों को फरार बता दिया। जबकि वाहन में बैठे दो व्यक्ति में से वाहन चालक करीब 2 घंटे तक वाहन के पास ही खड़ा रहा। वही एक व्यक्ति भाग निकला था। इतना ही नही शराब की गाड़ी लोड कराने वाला विनोद नायक मौके पर पहुंचा और ग्रामीणों को लुभाने का प्रयास किया ।

वही माफिया के गुर्गे विनोद नायक ने मौके पर पहुंचकर उक्त मामले में 3 दिसंबर को गोवा में बैठकर पुलिस को अपनी अंगुलियों पर नचाने वाले सेठ उर्फ शराब माफिया अलकेश बाकलिया का हवाला देकर कहा कि, सेठ से बात हुई जो अभी गोवा में है कहा और गोवा से आकर ग्रामीणों से मिलने की बात कही और फोन नंबर लेकर बात करने की बात कही। वहीं उक्त बातों का वीडियो होने पर बौखलाया शराब माफियाओं का गुर्गा विनोद नायक कहने लगा वीडियो मत बनाओ। लेकिन ग्रामीण मामले का प्रकरण बनाने पर तटस्थ रहे जिसके बाद विनोद नायक अपने वाहन में ही शराब से भरी गाडी चलाने वाले चालक को बिठाकर ले आया। पूरे मामले में उक्त शराब का मालिक व क्षेत्र में सप्लाई करने वाले विनोद नायक से लेकर वाहन चालक सभी की नामजद जानकारी आरोपियों की होने के बाद भी माफिया की रखैल कहीं जाने वाली आबकारी पुलिस ने अपनी रखेल रूपी गोरक्ति को कायम रख आरोपियों को फरार बता कर अज्ञात आरोपियों के नाम से प्रकरण दर्ज कर लिया गया। वही आबकारी ने प्रकरण बनाने के बाद जारी प्रेस नोट में शराब किस मार्ग पर, किस गांव में पकड़ी का भी उल्लेख नहीं कियां। शराब माफ्याओं की रखैल कहीं जाने वाली आबकारी पुलिस शराब माफ्या उर्फशराब ठेके का संचालन करने वाले अलकेश बाकलिया द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति का नाम देगा जो परिस्थितियों का मारा हो और जिसे जेल भेज प्रकरण का कोरम मात्र पूरा कर देगें।

गूंज प्रतिनिधि के मार्ग दर्शन मे ग्रामीणो ने मौके पर गाड़ी से सड़क पर शराब उतरवाकर बनवाया पंचनामा।

मौके पर पंचनामा बनाती आबकारी पुलिस।

क्षेत्र मे शराब भर कर अपने आका के आदेष का पालन करने वाला चालक शराब वाहन के पास खड़ा रहा।

गोल घेरे मे शराब माफिया अलकेश बाकलिया का गुर्गा विनोद नायक अपने साथियों के साथ पहुंचा मामले को रफा-दफा करवाने।

मुआवजे के नाम पर किसानों का मज़ाक उड़ाती सरकार ...

गैस लाईन कम्पनी के विरुद्ध एक जुट होंगे किसान, करेंगे उचित मुआवजा राशि की मांग

किसानों को नही पता पचास से सत्तर फीट तक नहीं कर सकेंगे पक्का निर्माण

40 बॉय 300 फिट खेत का 4 हजार रुपये दिया कम्पनी ने मुआवजा।

माही की गूंज, पेटलावद।

कांडला गुजरात से गोरखपुर उत्तरप्रदेश तक अंडरग्राउंड गैस लाईन बिछाने का कार्य फूलमाल से कल्याणपुरा, देदला, मुंडट झावलिया, रल्यावन, सोयला, रताम्बा, बनी होते हुए बेकल्दा तरफ जा रही, गैस पाइपलाइन कम्पनी द्वारा लाइन बिछाने का कार्य जोरो से चलाया जा रहा है, जों की पेटलावद विकास खण्ड से होकर गुजर रही गैस लाइन में क्षेत्र के किसानों की कृषि भूमि से निकल रही लाइन के लिए सरकारी गाइड लाइन से मुआवजा राशि भी दी गई। लेकिन मुआवजे के नाम पर किसानों का मज़ाक उड़ाया गया और किसानों को उनकी भूमि में से लाइन निकालने के बदले 150 रुपये से लेकर एक हजार रुपये तक का मामूली मुआवजा दिया।

झावलिया के किसानों को 40 फीट चौड़े और 300 फिट लम्बे खेत को कम्पनी ने लाइन बिछाने के लिए खाली करवाया, जिस पर गेहूं की फसल भी बौ दी गई थी, लेकिन कम्पनी ने किसान को चार हजार रुपये का मामूली भुगतान किया गया। ऐसा एक-दो नही सभी किसानों के साथ कम्पनी के द्वारा किया गया है। मामले की जानकारी गूंज को मिलने के बाद मामले को प्रमुखता से पिछले अंक मे उठाया था। जिसके बाद अब किसान सही मुआवजे दिए जाने के लिए जल्द ही सरकार से मांग कर प्रशासन से गुहार लगाएंगे कि बात कह रहे है।

किसानों को नही पता लाइन के आस-पास नही कर सकेगें पक्का निर्माण

वैसे तो गैस लाइन अंदर ग्राउंड बिछाई जा रही है, लाइन डलने के बाद किसान उसकी जमीन को कृषि उपयोग में फिर से ले सकेगा लेकिन किसानों को ये नही पता है। यदि कोई किसान खेत में मकान बनाना या ट्युबवेल करवाना चाहता है तो लाइन के आस-पास 50 से 70 फीट क्षेत्र में ये कार्य नही कर पायेगा, लेकिन ज्यादातर किसानों को इस बारे में कोई जानकारी नही दी गई कि, भविष्य में लाइन खराब होने की दशा में कम्पनी के वाहनों ओर मशीनों के आने-जाने के लिए जगह चाहिये। ऐसी परिस्थिति में यदि किसान के खेत मे फसल लगी हुई होगी तो कम्पनी के वाहन उसे आने-जाने और लाइन सुधारने के दौरान नुकसान पहुचा सकेंगे, जिसका कोई हर्जाना किसानों को नही मिलना है। कृषक निर्धारित क्षेत्र में निर्माण आदि कार्य नही कर पायेगा, अंडरग्राउंड लाइन के नाम पर मामूली मुआवजा देकर किसानों की खेती के बड़े हिस्से को कम्पनी ने अप्रत्यक्ष रूप से अपने कब्जे में कर लिया है।

स्थानीय चुनावों मे उठाना पड़ेगा नेताओं को नुकसान, कांग्रेस ने भी नही दिया साथ

साल के अंत और नए साल के पहले हफे में स्थानीय ग्राम पंचायत सहित जनपद ,जिला पंचायत के चुनाव होना है। खाद की भारी किल्लत से जूझ रहे पेटलावद विकास खण्ड की लगभग 20 से भी ज्यादा पंचायतो से गैस पाइपलाईन निकल रही है, जिससे किसानो को भारी नुकसानी उठानी पड़ी है, किसानों की समस्याओं को लेकर न तो भाजपा के जनप्रतिनिधि किसानो के साथ खड़े हुए न नही कांग्रेस ने विपक्ष की भूमिका निभाते हुए किसानों की हो रही नुकसानी की भरपाई के लिए कोई आवाज़ अब तक नही उठाई। क्षेत्र की जिला पंचायत सदस्य कलावती गेहलोत का कहना है कि, वो किसानों को उचित मुआवजा दिलवाने की मांग करेगी ।

पब्लिक लेंड प्रोटेक्शन सेल (पीएलपीसी) का गठन केवल दिखावे के लिए, थांदला-बदनावर स्टेट हाइवे की सरकारी भूमि क्यों नही की जा रही अतिक्रमण मुक्त

जादूगर पटवारी और राजस्व विभाग ने रिकॉर्ड में की बड़ी हेराफेरी, सरकारी नम्बरों के सीमांकन से हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी

माही की गूंज, पेटलावद। राकेश गेहलोत

स्टेट हाइवे क्रमांक 69 थांदला-बदनावर मार्ग पर स्थित शासकीय भूमि पर भूमाफ्या के कब्जे व दलालो द्वारा पटवारी और राजस्व विभाग के अधिकारियों से मिली भगत कर सरकारी नम्बरों में हेराफेरी का गूंज द्वारा खुलासा होने के बाद जमीनखोर दलालों सहित सरकारी रेकॉर्ड में हेराफेरी निजी भूमि के आड़ में बेशकीमती सरकारी जमीन कब्जाने वाले खरीददारो में घबराहट का माहौल है। भाजपा सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान रैली और सभाओं में लगातार भूमाफ्याओ को जमीन के दस फीट नीचे गाड़ने का दावा कर सुखियाँ बटोरते रहते हैं, लेकिन झाबुआ जिले का प्रशासन मुख्यमंत्री के दावे की हवा निकाल कर सरकार को ही बदनाम कर रहे हैं, ग्राम करडावद में स्टेट हाइवे से लगे शासकीय नम्बरों सहित कई विभागों को आवंटित भूमि पर अतिक्रमण हो चुका है जिसकी शिकायत के बाद अतिक्रमण होना पाया जा चुका है। लेकिन राजस्व विभाग अभी तक अतिक्रमणकर्ताओ की हाथ की कठपुतली बना हुआ है। जिसके चलते इन बेशकीमती सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त नही किया जा सका है।

सार्वजनिक भूमि/जमीनों पर अतिक्रमण हटाने हेतु पब्लिक लेंड प्रोटेक्शन सेल (पीएलपीसी) का गठन

पिछले दिनों कलेक्टर सोमेश मिश्रा की अध्यक्षता में सार्वजनिक भूमि/जमीनों पर अतिक्रमण हटाने के संबंध में बैठक आयोजित की गई थी जिसमें कलेक्टर मिश्रा द्वारा गठित समिति के सदस्यों को आवश्यक निर्देश दिए। इस बैठक में अपर कलेक्टर जे.एस. बघेल, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पेटलावद शिशिर गेमावत, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व झाबुआ एल.एन.गर्ग एवं समस्त अनुभाग के तहसीलदार उपस्थित थे। बैठक में मिश्रा ने बताया कि, सार्वजनिक भूमि/जमीनों पर अतिक्रमण के मामले को लेकर हाईकोर्ट में आए दिन बडी संख्या में जनहित याचिकाए दायर होती है। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने स्थानीय स्तर पर ऐसी ही शिकायतों का समाधान करने के लिए सभी जिलों में पब्लिक लैंड प्रोटेक्शन सेल का गठन करने के आदेश दिए है।

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेशानुसार राज्य सरकार राज्य के प्रत्येक जिले के ग्रामीण क्षेत्र की भूमियों के लिए सार्वजनिक भूमि संरक्षण प्रकोष्ठ पब्लिक लेंड प्रोटेक्शन सेल (पीएलपीसी) का गठन करने के आदेश दिए है। इसके लिए हर जिले में जिला कलेक्टर की निगरानी एवं अध्यक्षता में सेल का गठन किया गया है। इस सेल में अपर कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर(शिकायत शाखा प्रभारी), अधीक्षक भू-अभिलेख, मुख्यालय की तहसील का तहसीलदार सदस्य हैं। इस सेल में प्राप्त शिकायतों की जांच राजस्व अधिकारी/तहसीलदार करेंगे और शिकायत सही पाए जाने पर अतिक्रमण को तुरंत हटाने की कार्रवाई की जाएगी और इसकी जानकारी शिकायतकर्ता को देंगे। इस प्रक्रिया का उद्देश्य इस तरह के सार्वजनिक भूमि/जमीनों पर अतिक्रमण के मामले रोकना है। ताकि आमजन को बेवजह अदालती प्रक्रिया से नहीं गुजरना पडे और स्थानीय स्तर पर राहत मिल जाए। इस तरह आमजन को कोर्ट की खर्चिली और लम्बी कार्रवाई से बचने के लिए पी.एल.पी.सी. बनी है।

सरकार को गुमराह करने के लिए हो रहा दिखावा, अकेले पेटलावद राजस्व में अटके कई मामले

पब्लिक लेंड प्रोटेक्शन सेल (पीएलपीसी) का गठन कर जिला कलेक्टर भले ही वाह-वाही लूट कर सरकार को गुमराह कर रहे हो, लेकिन इस सेल का वास्तविकता से कोई लेना-देना नही है, बात करे पेटलावद राजस्व विभाग की तो वर्तमान में अतिक्रमण के कई मामले विभाग में अटके पड़े हैं जिसमे ताज़ा मामला स्टेट हाइवे का भी हैं। मामले को राजस्व विभाग उस प्रक्रिया से निपटा रहा है, जिस परेशानी से बचने के लिए सेल का गठन किया गया है। जबकि पब्लिक लेंड प्रोटेक्शन सेल (पीएलपीसी) के माध्यम से तुरंत निपटारा करने के निर्देश दिए जा चुके हैं, लेकिन कई प्रकरण में आदेश होने के बाद भी अतिक्रमण नही हटाये जबकि न्यायालय से किसी प्रकार का स्टे या रोक नही लगी हुई है, फिर भी मामले को न्यायालय में बता कर मामलो को दबाया जा रहा है।

राजस्व अधिकारी और जादूगर पटवारी की भूमिका संदिग्ध

पूरे मामले में गूंज द्वारा जल्द ही खुलासा किया जाएगा कि, स्टेट हाइवे के किन-किन सरकारी नम्बरों पर वर्तमान में अतिक्रमण किया हुआ है ,लेकिन ये बात राजस्व की मुख्य कड़ी हल्का पटवारी की जानकारी में नही है, ऐसा नही है इन सब अतिक्रमण के पीछे पटवारी का बड़ा योगदान है जो किसी न किसी तरीके से निजी भूमि से लगी शासकीय भूमि पर कब्जा करवाने में सहयोग करते हैं। पेटलावद राजस्व विभाग में जादूगर पटवारी के नाम से प्रसिद्ध चन्द्रावत पटवारी अपना खेल यहां भी खेल रहा है और इस सरकारी भूमि की बंदरबाट में अधिकारियों की मुख्य कड़ी बन गया है, शिकायत के बाद पिछले पटवारी की हेराफेरी पर पर्दा डाल कर अपना और अधिकारियों का उल्लू सीधा किया जा रहा है।

शराबियों का अड्डा बना स्कूल परिसर, रोज रात में स्कूल के स्टेज पर सजती है महफिल

माही की गूंज, बामनिया। शिक्षा का मंदिर जहा बच्चों को अपना अच्छा भविष्य गढ़ने के लिए भेजा जाता है, वहां कुछ असामाजिक तत्वों और नशेड़ियों ने शिक्षा के मन्दिर को अय्याशी का अड्डा बना दिया है। यहां बामनिया स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में आय दिन बच्चों और शिक्षकों को इस स्थिति का सामना करना पड़ता है की, खुद को शर्म आ जाये, यहां लगभग हर रात में नशा प्रेमी शराब की बोतलों और खाने-पीने के सामान के साथ सुनसान जगह की चाह में पहुँच जाते हैं, और स्कूल में बने प्रार्थना के मंच पर बैठ कर शराब पीते हैं, ये शराबी शराब पीने के बाद स्टेज और स्कूल परिसर में खाली बोतलों को फेक कर चले जाते हैं तो कई बार नशेड़ी शराब की बोतलों को तोड़ कर कांच बिखेर के चले जाते हैं। जिससे स्कूल में आने वाले बच्चों को चोट लगने का डर हमेशा बना रहता है, स्कूल प्रशासन की और से लम्बे समय से चली आ रही इस परिपाटी को रोकने की कोई पहल नही की गई है, जिससे इन नशेड़ियों को यहां आने से रोक पाना मुश्किल हो रहा है। कहने को स्कूल में रात को चौकीदार भी होता है लेकिन शराबियों से विवाद की स्थिति को देखते हुए चौकीदार बोल नही पाता, स्कूल प्रशासन को इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि स्कूली बच्चों पर इनका दुष्प्रभाव पड़ रहा है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, अलका भटेवरा द्वारा काम्पेक प्रिन्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, 3/54, प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 499, बाजना मार्ग, गणेश मंदिर के सामने, खवासा, तहसील थांदला, जिला-झाबुआ (म.प्र.) से प्रकाशित। प्रधान संपादक- संजय भटेवरा, संपादक- धर्मेन्द्र पंचाल । मोबाइल नं. -95898-82798 (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र झाबुआ रहेगा) आरएनआई नंबर- एमपीएचआईएन/2018/76422